

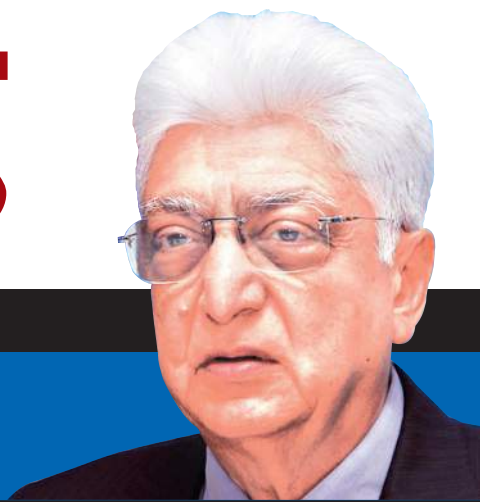
बुधवार 18 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com



एक नज़र

मूडीज ने घटाया भारत का वृद्धि अनुमान

रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कोरोना से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के मद्देनजर वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटकर 5.3 फीसदी कर दिया है। मूडीज ने पहले इसके 6.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया था लेकिन फरवरी में इसे घटकर 5.4 फीसदी कर दिया था। एजेंसी ने कहा कि कोरोनावायरस का अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर हो सकता है। प्रभावित देशों में इससे घरेलू मांग पर असर हो रहा है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है तथा विदेशी व्यापार घट रहा है।

न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण के मुद्दे पर कमलनाथ सरकार से बुधवार तक जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति और विधान सभा के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किए। गज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ को 16 मार्च को सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहा था लेकिन प्रजापति ने कोरोनावायरस का हवाला देते हुए सदन में शक्ति परीक्षण करायें बिना ही सोमवार को सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी।

गोएयर ने बंद की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

घरेलू विमानन कंपनी गोएयर ने कोरोनावायरस संकट के मद्देनजर 17 मार्च से 15 अप्रैल तक अपनी सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद करने की घोषणा की है। उड़ानों की संख्या में कमी के कारण कंपनी क्रमिक आधार पर अपने कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेजेगी। कोरोनावायरस के कारण कई देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं। इससे वैश्विक हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। गोएयर ने कहा कि इन उपायों से उसे उड़ानों की संख्या में कटौती के असर से निपटने में मदद मिलेगी।

कोविड-19 के कारण कई रेलगाड़ियां रद्द

मध्य रेलवे ने मंगलवार को कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ते खतरे से निपटते हुए 23 रेलगाड़ियां रद्द कर दीं। पश्चिम रेलवे ने भी 1 अप्रैल तक के लिए 5 रेलगाड़ियां रद्द करने की घोषणा की है। संक्रमण फैलने के डर से यात्रियों की संख्या में भी भारी कमी देखी गई है। बुधवार से रेलगाड़ियां रद्द होने की घोषणा प्रभावी हो जाएगी। इस बीच, रेलवे प्लेटफॉर्म में भीड़ में कमी लाने के लिए रेलवे के कुछ मंडलों ने प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है।

कोरोना से 137 में संक्रमण की पुष्टि, 5,700 पर नजर

एजेंसियां
नई दिल्ली, 17 मार्च



कई राज्यों से कोरोनावायरस के नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या आज बढ़कर 137 पहुंच गई। इनमें 24 विदेशी नागरिक और तीन मृतक भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन लोगों के संपर्क में आए 5,700 लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। मुंबई में आज एक व्यक्ति की मौत के बाद देश में इससे मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर लोगों ने गैर जरूरी यात्रा से परहेज नहीं किया तो ट्रेन और बस सेवाओं को बंद करने का कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने भवनों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगाने और आगंतुकों को अस्थायी एवं विजिटर पास जारी करना तत्काल प्रभाव से स्थगित करने को कहा। सरकारी इमारतों में स्थित जिम, मनोरंजन केंद्र और शिशु देखभाल केंद्रों को बंद करने का निर्देश भी दिया गया है। सरकार ने दवा कंपनियों से मास्क, दस्ताने और सैनेटाइजर्स के उत्पादन एवं बिक्री के बारे में बुधवार तक ब्योरा देने को कहा है।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 12



पृष्ठ 6

जिंसों में गिरावट जारी

अजीम प्रेमजी

पृष्ठ 3

मार्च तिमाही में विप्रो पर नहीं पड़ेगा कोरोना का असर

येस बैंक के पास पर्याप्त नकदी

8,500 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद, दूसरे दौर में जुटाएगा 10 हजार करोड़ रुपये

सुब्रत पांडा और अभिजित लेले
मुंबई, 17 मार्च

संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के ऋणदाता येस बैंक को अगले वित्त वर्ष में चुककर्ता कंपनियों से 8,500 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद है। साथ ही बैंक वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान दूसरी किस्त से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई इक्विटी जुटाने की भी योजना बना रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) येस बैंक को संकट उबारने की योजना की अगुआई कर रहा है और वह अगले तीन साल तक इसके करीब 49 फीसदी शेयर अपने पास रखेगा। पुनर्गठन योजना के मुताबिक एसबीआई येस बैंक में 26 फीसदी हिस्सेदारी की तीन साल तक बेच नहीं पाएगा। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'तीन साल तक हम येस बैंक में एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। इस दौरान हमें अपने निवेश पर टीकटाक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। किसी को भी मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'

येस बैंक के कामकाज पर लगी



येस बैंक के प्रशासक प्रशांत कुमार और एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार।

निकट अवधि की प्राथमिकताएं

- खुदरा जमा का बेहतर उपयोग
- एमएसएमई सहित खुदरा ऋण पर जोर
- दबाव वाली संपत्तियों के समाधान में तेजी लाना
- लागत को कम करना

पाबंदी हटाने से एक दिन पहले मीडिया से मुखातिब हुए बैंक के प्रशासक प्रशांत कुमार ने कहा कि बैंक ने निकासी में तेजी की किसी भी स्थिति से निपटने के

लिए पर्याप्त तैयारी की है। उन्होंने कहा, 'हमारे सभी एटीएम और शाखाओं में नकदी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और हम बाहर से नकदी की जरूरत नहीं



पड़ेगी। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है।' इससे पहले शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर येस बैंक को नकदी की मदद की जाएगी। आने वाले दिनों में बैंक थोक जमा पर निर्भरता कम करने के लिए खुदरा जमा पर जोर देगा। प्रशांत कुमार ने कहा, 'हमारी प्राथमिकता खुदरा जमा आधार बनाने की होगी। हमारे कुल ऋण में 60 फीसदी हिस्सा खुदरा ऋण और बाकी हिस्सा कॉर्पोरेट ऋण का होगा। अभी बैंक के कुल ऋण में 60 फीसदी हिस्सा कॉर्पोरेट ऋण का है और 40 फीसदी खुदरा ऋण का है।'

येस बैंक के लिए पहले दौर की फंडिंग के बारे में एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि इसके लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध थी लेकिन यह फैसला किया गया कि इसमें घरेलू बैंक हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, बहुत कम समय में ही कई अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन इससे बैंक को लंबे समय तक पाबंदी से गुजरना पड़ता। लेकिन हम जल्दी से जल्दी पाबंदी को हटाकर स्थिति को सामान्य करना चाहते थे।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्राइवेट लैब में भी कोविड-19 की जांच

सोहिनी दास
मुंबई, 17 मार्च

सरकार ने मंगलवार को निजी लैब्स को कोरोनावायरस के नए मामलों की जांच करने की इजाजत दे दी। सरकार के इस निर्णय से वे लोग अपनी जांच करा पाएंगे, जिन्हें संक्रमण होने का अंदेश है। हालांकि जांच शुल्क पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन देश के शीर्ष दवा शोध संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा है कि वह निजी लैब से निःशुल्क जांच करने की अपील करेगा।

उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार



- आईसीएमआर ने की प्राइवेट लैब से मुफ्त जांच की अपील
- कोविड-19 की जांच के लिए आईसीएमआर ने 49 नई प्रयोगशालाएं करेगी सक्रिय
- मरीजों को नहीं जाना होगा लैब, घर से लिए जाएंगे सैंपल

कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच पर 9,000 से 12,000 रुपये तक खर्च आ सकता है, जो किट के प्रकार और इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। इस समय कोविड-19 के लिए जांच किट

पर काम तेजी से हो रहा है। इस कारोबार से जुड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के अनुसार शुल्क तय करने की तैयारी हो

रही है। इस बारे में एक निजी कंपनी ने कहा, 'अगर रसायन 3,000 रुपये में उपलब्ध होगा तो जांच शुल्क बिना किसी लाभ के 9,000 रुपये का आएगा।' इस बीच, देश की शीर्ष जांच कंपनियों के शेरों में तेजी देखी गई। डॉ. लाल पैथलैक्स का शेयर मंगलवार को प्रति शेयर 3 प्रतिशत चढ़कर 1,500 रुपये पर बंद हुआ, जबकि मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर भी 2.4 प्रतिशत तक उछल गया।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड-19 के लिए वह देश भर में 51 नेशनल एंक्रीडिटेशन बोर्ड सक्रिय करेगा।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

वैश्विक मंदी के डर से बिकवाली हावी

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 17 मार्च

शेयर बाजार में राहत के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि विदेशी निवेशक वैश्विक मंदी की आशंका में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बेंचमार्क निफ्टी करीब तीन साल बाद आज पहली बार 9,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स 30,000 के स्तर को बनाए रखा। पिछले दो दिन में निफ्टी करीब 1,000 अंक टूट चुका है और सेंसेक्स करीब 3,500 अंक नीचे आया है।

सुबह के कारोबार में बाजार अच्छी बढ़त पर खुला था जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन कारोबार के दौरान काफी उतार चढ़ाव बना रहा और सेंसेक्स 658 अंक चढ़ने के बाद कारोबार की समाप्ति पर 811 अंक लुढ़ककर 30,579 पर बंद हुआ। निफ्टी 230 अंक नीचे 8,967 पर बंद हुआ, जो मई 2017 के बाद इसका निचला स्तर है।

आर्थिक वृद्धि पर कोरोनावायरस के असर और कंपनियों की आय की चिंता से बाजार में गिरावट बढ़ी। हर दिन कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है और स्थिति को काबू में करने के लिए वैश्विक स्तर पर कामकाज बंद करने का भी जोखिम बना हुआ है। कोरोनावायरस से दुनिया भर में अब तक 1.74 लाख लोग संक्रमित हैं और करीब 7,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्वव्यापी महामारी के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली हो रही है और सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों के तमाम उपायों के बावजूद मंदी की चिंता बढ़ गई है।

मार्गिन स्टेनली ने कहा, 'अधिकतर सरकारें और निजी क्षेत्र की कंपनियां वायरस से बचने के लिए सख्त सामाजिक अलगाव जैसे उपाय कर रही हैं, जिससे गंभीर आर्थिक नुकसान होने का खतरा है।'

फ्रांस, इटली और स्पेन ने शॉट सेंलिंग पर रोक लगा दी है, वहीं कुछ छोटे बाजारों ने अपने वित्तीय बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रा को अदला-बदली और बाजार में तरलता बढ़ाने के उपायों की घोषणा की है। बहुत सारे निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्रीय बैंक जल्द ही दर में कटौती की घोषणा कर सकता है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दर में कटौती की थी और सोमवार को एशिया के कई केंद्रीय बैंकों ने भी दरें घटाने की घोषणा की थी। सेंसेक्स के करीब दो-तिहाई शेयर नुकसान पर बंद हुए। आईसीआईआई बैंक और इंडसइंड बैंक में करबी 9 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि हिंदुस्तान यूनिटीवर और एशियन पेंट्स में 3-3 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 3



किसे फायदा, कौन नुकसान में

| | 17 मार्च | % बदलाव* |
|---------------|----------|----------|
| इंफोसिस | 2,009.0 | 3.5 |
| टीसीएस | 1,839.2 | 3.1 |
| एशियन पेंट्स | 1,734.2 | 3.0 |
| पावरग्रिड | 162.2 | 2.5 |
| मारुति सुजुकी | 5,604.0 | 2.1 |
| इंफोसिस | 366.9 | -8.9 |
| इंडसइंड बैंक | 604.3 | -8.9 |
| बजाज फाइनेंस | 3,444.9 | -6.3 |
| एचडीएफसी | 1,754.8 | -4.7 |
| इंफोसिस | 555.6 | -4.7 |

वीएसई- क्षेत्रवार सूचकांक

| | 17 मार्च | % गिरा* |
|----------------|----------|---------|
| वीएसई बैंकेक्स | 25,293 | -4.5 |
| वीएसई फाइनेंस | 4,966 | -4.4 |
| वीएसई दूरसंचार | 1,039 | -3.5 |
| वीएसई आईटी | 11,893 | -3.0 |
| वीएसई रियल्टी | 1,604 | -2.5 |

*पिछले दिन के बंद भाव के मुकामले
स्रोत : ब्यूरोवर्ग

आज का सवाल

क्या कोरोना संकट से वैश्विक मंदी का बड़ेगा खतरा?

www.bshindi.com पर राय भेजें।

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या मौजूदा हालात में आरबीआई को तत्काल घटानी चाहिए दरें?

हां **55.56%**
नहीं **44.44%**

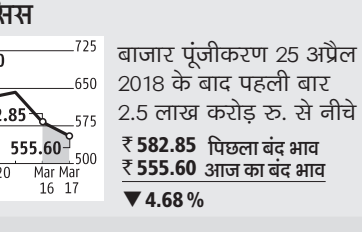
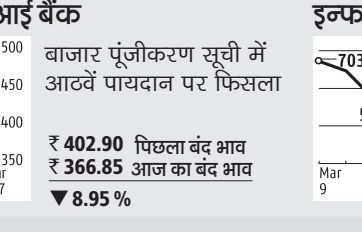
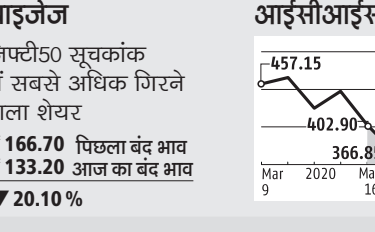
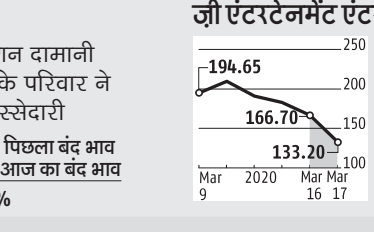
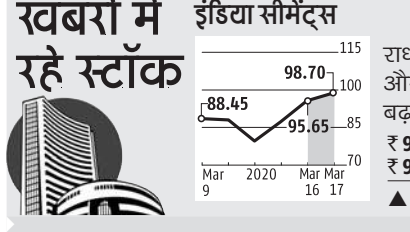
व्यापार गोष्ठी

महामारी से निपटने को कितने तैयार हम ?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पत्ते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिजनेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bshindi.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

2 बैंकिंग क्षेत्र



संक्षेप में

पुणे मेट्रो के कोच बनने में होगी देरी, कारखाना बंद

इटली की टोटागढ़ फिरेमा को पुणे मेट्रो के एल्युमीनियम कोच के नमूने के विनिर्माण में देरी होगी। इटली में कोरोना वायरस महामारी के भीषण प्रकोप की वजह से वहां उसके संयंत्र में काम बंद है। इटली में इन डिब्बों का विनिर्माण टोटागढ़ फिरेमा कर रही है। यह कंपनी कोलकाता की टोटागढ़ वेगन्स कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टोटागढ़ वेगन्स के एक अधिकारी ने यहां मंगलवार को कहा कि मेट्रो कोच के नमूने के विनिर्माण का उद्घाटन पहले 8 अप्रैल को संभावित था। लेकिन इटली सरकार के दिशानिर्देशों के बाद कंपनी ने अपना कारखाना 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है।

भाषा

ओएनजीसी ने केजी ब्लॉक से गैस उत्पादन शुरु किया

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी स्थित सबसे महत्वपूर्ण कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक से गैस का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी आने वाले सप्ताह में उत्पादन बढ़ाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कंपनी के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिहाज से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। केजी– डीडब्ल्यूएन–98–2 यानी केजी– डी5 ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज के उत्पादन के लिहाज से मंद पड़ते केजी–डी6 ब्लॉक से लगता हुआ क्षेत्र है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने केजी–डी5 ब्लॉक से उत्पादन शुरू कर दिया है। वर्तमान में इस ब्लॉक से यह ढाई लाख घनमीटर प्रतिदिन का उत्पादन कर रही है।

भाषा

इंडसइंड, आरबीएल बैंक: जोरिवम का असर

हंसिनी कार्तिक मुंबई, 17 मार्च

इंडसइंड बैंक और **आरबीएल बैंक** के शेयरों की कीमत एक महीने में घटकर लगभग आधी रह गई है और एक साल में इनमें 65-75 प्रतिशत के बीच

गिरावट आई है। परिसंपत्ति गुणवतता और ऋण वृद्धि से जुड़ी चिंताओं से निवेशक धारणा प्रभावित होने से इन शेयरों में चमक फीकी पड़ी है। मौजूदा स्तर पर, आरबीएल बैंक का शेयर अपने सर्वाधिक निचले स्तर के नजदीक और इंडसइंड बैंक 6 साल

के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक के प्रबंधन द्वारा एक सप्ताह पहले यह स्पष्ट किया गया था कि बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत है। आरबीएल ने भी मंगलवार को मीडिया को जारी किए बयान में कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है, हालांकि उसने पिछले सप्ताह जमाओं में 3 प्रतिशत की कमी दर्ज की। येस बैंक के घटनाक्रम से निवेशकों का भरोसा डगमगाने से इन शेयरों और बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव पड़ रहा है।

एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म के शोध प्रमुख का कहना है कि विदेशी निवेशक बैंकिंग शेयरों पर सतर्कता बरत रहे हैं, जबकि एसएमसी कैपिटल के सिद्धार्थ पुरोहित का मानना है कि इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक ज्यादा जोखिम के उदाहरण हैं। आरबीएल बैंक का ऋण भी परिसंपत्ति गुणवत्ता में कमजोरी से जुड़ा हुआ है।

येस बैंक के पास पर्याप्त नकदी पृष्ठ 1 का शेष...

रजनीश कुमार ने कहा, एक ही बार में पूरी पूंजी जुटाने के बजाय दो चरणों में इसे पूरा किया जा सकता है। 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने से यह सुनिश्चित होगा कि बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात के सभी मानकों को पूरा कर रहा है। प्रशांत कुमार ने कहा कि पहले दौर की फंडिंग से न्यूनतम नियामकीय जरूरतें पूरी होंगी और दूसरी किस्त से जुटाई गई

नया येस बैंक

| | पूंजी ढांचाशेयरों की संख्या (अरब में) | शेयर मूल्य (रुपये में) | बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये में) |
|--|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| वर्तमान पूंजी निवेश के बाद* | 2.55 | 59 | 15,000 |
| | निवेश (करोड़ रुपये में) | हिस्सेदारी (फीसदी में) | |
| एसबीआई | 6,050.0 | 48.21 | |
| आईसीआईसीआई बैंक | 1,000.1 | 7.97 | |
| एचडीएफसी | 1,000.0 | 7.97 | |
| एक्सिस बैंक | 600.0 | 4.78 | |
| कोटक | 500.0 | 3.98 | |
| फेडरल बैंक | 300.0 | 2.39 | |
| बंधन बैंक | 300.0 | 2.39 | |
| आईडीएफसी फर्स्ट एलआईसी | 250.5 | 1.64 | |
| <small>स्रोत: बीएसई, *वर्तमान मूल्य और नए शेयर के लिए निर्गम मूल्य पर आधारित</small> | | | |

निवेशकों का भरोसा बढ़ा। दूसरा, मौजूदा व नए जारी शेयरों के 75 फीसदी हिस्से की बिक्री पर तीन साल साल की विवादस्पद पाबंदी। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि शुक्रवार के कारोबार में 16 फीसदी सुधार से पहले निफ्टी 10 फीसदी टूट गया था। कई बैंकिंग व वित्तीय शेयर उस कारोबारी सत्र में 30 फीसदी से ज्यादा चढ़े-उतरे थे, जो ट्रेडरों के लिए अहम बन गया।

बाजार में खास तौर से वित्तीय शेयरों के

लिए कमजोर बाजार अवधारणा के बाद भी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद येस बैंक के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन थे। सप्ताहांत में सरकार ने पुनर्गठन योजना की विस्तृत जानकारी दी, जिसके तहत एसबीआई येस बैंक की 48.2 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 6,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा, वहीं आईसीआईसीआई बैंक व एचडीएफसी 8-8 फीसदी हिस्सेदारी के लिए क्रमशः 1,000-1,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा। इस बीच,

निजी बैंक के बीच धुवीकरण

कोरोनावायरस के डर से बैंक शेयरों में भारी गिरावट के कारण निजी क्षेत्र के शीर्ष बैंकों और छोटे बैंकों के मूल्यांकन में भारी अंतर पैदा हो गया है। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों के बाजार पूंजीकरण में 20 फरवरी 2020 से बाजार में गिरावट शुरू होने के बाद अब तक औसतन 23.4 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन इस दौरान कई छोटे बैंकों को करीब एक तिहाई बाजार पूंजीकरण का झटका लगा है। आरबीएल बैंक को इस दौरान 47.2 फीसदी का झटका लगा। उसका बाजार पूंजीकरण 20 फरवरी को 15,700 करोड़ रुपये था जो घटकर 16 मार्च के बंद भाव के अनुसार 8,282 करोड़ रुपये रह गया। दूसरी ओर, इंडसइंड बैंकके बाजार पूंजीकरण में इस दौरान 44 फीसदी घटकर 46,000 रुपये रह गया जो करीब तीन सप्ताह पहले 82,000 करोड़ रुपये था। इस दौरान जिन अन्य बैंकों के बाजार पूंजीकरण में 30 फीसदी से अधिक का झटका लगा है उनमें बंधन बैंक, ऐक्सिस

बैंक, आईडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक और कर्णाटक बैंक शामिल हैं। जबकि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक और डीसीबी बैंक का प्रदर्शन अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर रहा। येस अवधि में इन बैंकों के बाजार पूंजीकरण में 18 से 19 फीसदी की गिरावट आई। विश्लेषकों का कहना है कि इससे शीर्ष बैंकों औ अन्य बैंकों के बीच धुवीकरण दिखेगा। शेयर मूल्य में इन बैंकों के बाजार पूंजीकरण में 18 से 19 फीसदी की गिरावट आई। ऐसे में उनकी बाजार हिस्सेदारी खिसक सकती है।येस बैंक प्रकरण के कारण बैंकों के लिए अतिरिक्त टियर-1 पूंजी जुटाना पहले ही कठिन हो गया है। दोहरी मार के कारण बैंकों की पूंजी लागत बढ़ जाएगी जिससे उद्योग की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। दिलचस्प है कि येस बैंक ने अपने बाजार पूंजीकरण में 5 फीसदी की वृद्धि के साथ इस अवधि में दमदार प्रदर्शन किया। *कृष्णाकांत*

पूंजी में से 80 फीसदी राशि को बैंक की वृद्धि पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले दौर की फंडिंग में एसबीआई ने येस बैंक में इक्विटी के रूप में 6,050 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने हजार-हजार करोड़ रुपये, ऐक्सिस बैंक ने

600 करोड़ रुपये और कोटक बैंक ने 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। फेडरल बैंक और आईडीएफसी बैंक ने तीन-तीन सौ करोड़ रुपये लगाए हैं। कोलकाता के बंधन बैंक ने 250 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पुनर्गठन योजना के तहत इन बैंकों ने दो रुपये कीमत वाला शेयर दस रुपये में खरीदा है।

| बैंक | वर्तमान बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये में) | बाजार पूंजीकरण में अंतर (फीसदी में) | मूल्य एवं बुक वैल्यू का अनुपात |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| एचडीएफसी बैंक | 547,666.2 | -17.9 | 3.5 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 264,677.6 | -17.9 | 5.8 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 260,755.8 | -26.3 | 2.4 |
| एक्सिस बैंक | 143,640.4 | -31.5 | 1.7 |
| इंडसइंड बैंक | 46,001.5 | -43.9 | 1.4 |
| बंधन बैंक | 44,264.9 | -33.9 | 3.2 |
| सिटी यूनियन बैंक | 13,288.8 | -18.8 | 2.6 |
| आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 12,794.3 | -33.7 | 0.8 |
| फेडरल बैंक | 12,594.1 | -27.8 | 0.9 |
| आरबीएल बैंक | 8,282.9 | -47.2 | 1.1 |
| सभी निजी बैंक | 1,409,909.8 | -23.4 | 2.6 |
| <small>*20 फरवरी 2020 को बाजार में गिरावट शुरू होने के बाद बाजार पूंजीकरण में बदलाव। नोट- प्राइस टु बुक वैल्यू 16 मार्च के बाजार पूंजीकरण के आधार पर। बैंकों की शुद्ध हेसियत 30 सितंबर 2019 के अंत के अनुसार। स्रोत: कैपिटलाइन, संकलन: बीएस रिसेर्च ब्यूरो</small> | | | |

ऋण पर खड़ा कपूर का कारोबारी साम्राज्य

येस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक राणा कपूर और उनके परिवार की कंपनियों की भूलभुलैया, खासकर डूइट अर्बन वेंचर्स इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गहन जांच के दायरे में है। सीबीआई का आरोप है कि डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन ने डूइट अर्बन वेंचर्स को बिल्डर ऋण के रूप में रिश्वत दी थी। इसके बदले येस बैंक ने लघु अवधि डिवेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा दस्तावेज का अध्ययन किया जो एक दिलचस्प कहानी बयां करता है।

कंपनी रजिस्ट्रार के दस्तावेज से पता चलता है कि कंपनी आतिथ्य सेवा एवं बुनियादी ढांचा में अतिरिक्त कारोबार के साथ-साथ भारत और विदेश में जिंस कारोबार भी करती है। हाल के वर्षों में डूइट की किस्मत नाटकीय रूप से बदल गई। वर्ष 2018-19 में कंपनी ने 59 करोड़ रुपये के राजस्व पर 48.76 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया जबकि 2017-19 में उसने 43 करोड़ रुपये के राजस्व पर महज 2.7 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराए गए दस्तावेजों में कंपनी ने नुकसान को इस तरह जायज ठहराया है: कंपनी ने अपनी सहायक इकाइयों के जरिये आतिथ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्र के कारोबार में रणनीतिक गैर-चालू निवेश किया। इनमें से कुछ कारोबार फिलहाल आंशिक चरण में हैं और उन्हें मुनाफा कमाने के लिए लंबी अवधि से गुजरना पड़ेगा और इसलिए 31 मार्च 2019 के अनुसार उनके वित्तीय नतीजों में उल्लेखनीय संचित घाटा दर्ज किया गया है।

अपनी सहायक इकाइयों में इस प्रकार के आक्रामक निवेश के लिए डूइट ने ऋण का इस्तेमाल किया जो पिछले वर्ष के मुकाबले 2018-19 में दोगुना वृद्धि के साथ 600 करोड़ रुपये हो गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि डीएचएफएल ने डूइट को 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा दस्तावेजों के अनुसार, डूइट की कुल देनदारी 2017-18 में महज 1.86 करोड़ रुपये (क्योंकि उसने कोई अन्य ऋण नहीं लिया था) थी जो बढ़कर अगले वित्त वर्ष में 415 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018-19 में 602.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। परिणामस्वरूप इस दौरान कंपनी की ब्याज लागत 34 करोड़ रुपये से दोगुना वृद्धि के साथ 63 करोड़ रुपये हो गई।

आरबीएल बैंक

ने गंवाई 3 फीसदी

जमा रकम

सुब्रत पांडा मुंबई, 17 मार्च

निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने आज कहा कि संस्थागत जमाकर्ताओं और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा की गई निकासी के कारण पिछले सप्ताह उसे अपनी कुल जमा का करीब 3 फीसदी हिस्सा गंवाना पड़ा। वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में बैंक के पास कुल जमा रकम 62,907 करोड़ रुपये थी।

बैंक ने कहा है कि राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा जमा पूंजी की निकासी के मामलों को राज्य सरकारों के साथ एक-एक करके निपटایा जा रहा है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्योग के स्तर पर इन मामलों को निपटया जा रहा है। बैंक ने कहा, 'इसके बावजूद हमारे पास पर्याप्त खुदरा जमा, संस्थागत जमा, पुनर्वित्त एवं अतिरिक्त नकदी परिसंपत्तियों के साथ काफी नकदी उपलब्ध है।'

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह राज्य सरकारों को पत्र लिख कर कहा था कि वे अपनी जमा रकम को निजी क्षेत्र के बैंकों के इतर हस्तांतरित न करें क्योंकि निजी बैंकों के पास जमा रकम की सुरक्षा को लेकर जताई जा रही आशंकाएं बेबुनियाद हैं। आरबीएल बैंक ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार बयान जारी कर कहा है कि वह एक दमदार प्रशासन व्यवस्था के साथ वित्तीय तौर पर मजबूत, लाभप्रद और नकदी संपन्न बैंक है। बैंक ने यह भी कहा है कि बैंक की वित्तीय सेहत एवं स्थायित्व को लेकर बाजार की अफवाहों बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। एसी अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं।

आईटी फर्मों ने गंवाया बाजार पूंजीकरण

मांग में सुस्ती, आपूर्ति में अवरोध को इस बिकवाली की मुख्य वजह माना गया

देवाशिष महापात्र

बेंगलूरु, 17 मार्च

देश की तीन अग्रणी आईटी सेवा कंपनियों ने पिछले पखवाड़े संयुक्त रूप से करीब 31 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण गंवा दिया क्योंकि कोरोनावायरस से शेयर बाजार का टूटना जारी रहा।

वायरस के वैश्विक प्रसार को देखते हुए बाजार पूंजीकरण में गिरावट भारत तक सीमित नहीं है क्योंकि आईबीएम, एक्संचर और डीएक्ससी टेक्नोलॉजी समेत सभी वैश्विक आईटी सेवा दिग्गज कंपनियों ने भी अपने-अपने बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की।

2 मार्च से लेकर मंगलवार 17 मार्च तक देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस के बाजार पूंजीकरण में करीब 21 अरब डॉलर यानी 1.45 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने इस साल मांग सुस्त होने के अनुमान में पोजीशन की बिकवाली की।

इसी तरह देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बाजार पूंजीकरण में पिछले पखवाड़े करीब 7 अरब डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपये की कमी दर्ज हुई और उसका बाजार पूंजीकरण 2.36 लाख करोड़ रुपये रह गया। विप्रो की बात करें तो उसका बाजार पूंजीकरण करीब 3.7 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपये टूटकर मंगलवार को 98,902 करोड़ रुपये रह गया। वैश्विक स्तर पर स्थितियां अलग नहीं हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक तकनीकी कंपनी डीएक्ससी टेक्नोलॉजी का बाजार पूंजीकरण घटकर करीब 3 अरब डॉलर के आसपास रहा। ह्यूलेट पैकर्ड के एंटरप्राइज सेवा कारोबार से अलग होने वाली आईटी सेवा कंपनी ने पिछले साल बाजार पूंजीकरण में गिरावट देखी थी, जो पिछले तीन महीने में तेज हुई गई और सबसे

टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र के लिए साल रहेगा चुनौतीपूर्ण

अर्णव दत्ता

नई दिल्ली, 17 मार्च

जहां 2019 देश में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंसेज की निर्माता कंपनियों के लिए उम्मीद का वर्ष रहा था, वहीं चालू वर्ष में हालात अब प्रतिकूल हो गए हैं। जहां बढ़ते कराधान से आपूर्ति एवं मांग में समस्या पैदा हुई है, वहीं कई कारकों से इस क्षेत्र की संभावनाएं धूमिल हई हैं। कोरोनावायरस की महामारी अब पूरे देश में अपना प्रभाव डाल रही है जिससे उपभोक्ता बाजार पर दबाव दिख रहा है। निर्माता अब अनिश्चित भविष्य की आशंका देख रहे हैं। चूँकि लोग सार्वजनिक स्थानों और बाजारों से दूरी बना रहे हैं जिससे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटों जैसे बड़े उपकरणों के लिए मांग प्रभावित हो सकती है। पारंपरिक रूप से, केरल और तमिलनाडु में गर्मियां शुरू होने के साथ फरवरी तक एसी और रेफ्रिजरेटों की बिक्री शुरू हो जाती है। लेकिन कारोबार बंद रखे जाने से ये दक्षिण राज्य इस साल प्रभावित हुए हैं।

एसी की 50 प्रतिशत बिक्री फरवरी के मध्य से लेकर जुलाई तक होती है, लेकिन इस बार गर्मियां देर से शुरू होने की वजह से बिक्री पर दबाव पड़ सकता है।

दाइकिन इंडिया के प्रबंध निदेशक कंवलजीत जावा के

देसी उद्योग जगत में विलय-अधिग्रहण को झटका

खरीदार मौजूदा संकट का फायदा उठाते हुए कम मूल्यांकन पर दे सकते हैं जोर

देव चटर्जी

मुंबई, 17 मार्च

कोरोनावायरस ने भारतीय कंपनियों के विलय और अधिग्रहण योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाजार बुरी तरह गिरा हुआ है जिससे अधिकतर कंपनियों का मूल्यांकन को भी झटका लगा है। बैंकों का कहना है कि दुनिया भर में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा है और विदेश यात्रा से लौटे लोगों को अलग-थलग रखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय कंपनियां भी रकम जुटाने की अपनी बड़ी योजनाओं को फिलहाल टाल रही हैं।

बैंकों का कहना है कि भारत में कई बड़े अधिग्रहण के अवसर आ रहे हैं। इनमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) में केंद्र सरकार द्वारा 50 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री, एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) द्वारा अपने रिफाइनिंग एवं पेट्रोरसायन कारोबार में हिस्सेदारी की बिक्री सऊदी अरामको को करना शामिल है। बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया के करीबी एक बैंकर ने कहा, ‘इन सौदों के तहत अरबों डॉलर का सीमापार लेनदेन होना है। इस लिहाज से कोरोना वैश्विक महामारी गलत समय में फैली है और इससे इन सौदों में देरी हो सकती है।’

बड़े अधिग्रहण सौदों के अलावा कई ऐसी बिजली परियोजनाएं हैं जिनकी बिक्री भारतीय बैंकों द्वारा की जा रही है। इन परियोजनाओं के खरीदार भी विदेश से रकम

मूल्यांकन पर चोट



ज्यादा गिरावट पिछले एक महीने में देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी आोटी सेवा कंपनी और सालाना 21 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करने वाली कंपनी का बाजार पूंजीकरण घटकर एक चौथाी रह गया है। पारिख कंसल्टिंग के संस्थापक और आईटी आउटसोर्सिंग सलाहकार पारिख जैन ने कहा, कोरोनावायरस के वैश्विक प्रसार के साथ आईटी उद्योग नकारात्मक बढ़त दर्ज कर सकता है, जिसकी रफ्तार इस साल करीब 5 फीसदी रहने का अनुमान था। अब उद्योग –5 से 5 फीसदी के दायरे में बढ़त दर्ज कर सकता है। इससे निवेशक निश्चित तौर पर हतोत्साहित हुए हैं।

वैश्विक रिसर्च फर्म गार्टनर के मुताबिक, आईटी पर वैश्विक खर्च साल 2020 में 3.7 फीसदी बढ़ सकता है। हालांकि वायसस पर लगाम कसने के लिए बड़े देशों की तरफ से अपने प्रतिष्ठान बंद करने के उठाए जा रहे कदम के साथ मांग में सुस्ती अब वास्तविकता बन गई है। पारिख कंसल्टिंग के जैन ने कहा, तेल व गैस और ट्रेवल व हॉस्पिटैलिटी आईटी खर्च में करीब 40 फीसदी का योगदान करता है। ये क्षेत्र अब भारी

■ एक पखवाड़े में टीसीएस के बाजार पूंजीकरण में करीब 21 अरब डॉलर यानी 1.45 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई

■ इस अवधि में इन्फोसिस के बाजार पूंजीकरण में 7 अरब डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपये की कमी दर्ज हुई

■ विप्रो का बाजार पूंजीकरण करीब 3.7 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपये टूटकर मंगलवार को 98,902 करोड़ रुपये रह गया

अवरोध का सामना कर रहे हैं, लिहाजा बाजार पूंजीकरण में सुधार चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।

एक नोट में वैश्विक कंसल्टिंग फर्म एवरेस्ट ग्रुप ने कहा है कि यह स्थिति जून 2020 तक बनी रह सकती है। आउटसोर्सिंग एडवाइजरी फर्म एवरेस्ट ग्रुपु के संस्थापक व मुख्य कार्याधिकारी पीटर बेंडॉर-सैमुअल ने कहा, हमारा मानना है कि यह स्थिति एक तिमाही में मांग से जुड़े राजस्व की रफ्तार पर असर डालने जा रही है (जून तिमाही)। मांग में सुस्ती को देखते हुए सभी आईटी कंपनियां मौजूदा वर्ष में कीमत पर भारी दबाव का सामना करेंगी, चाहे कोरोनावायरस के प्रसार के कारण पैदा हुई स्थिति पर लगाम क्यों कसा जाता हो।

आईटी फर्म पहले ही बड़े सौदे हासिल करने में देरी का सामना कर रही है और रिपोर्ट बताती है कि इस महीने ही करीब 3–4 अरब डॉलर पर हस्ताक्षर को टाल दिया गया। पारिख कंसल्टिंग के जैन ने कहा, अगर आगामी तिमाहियों में मांग व आपूर्ति में सुधार होता है तो बाजार पूंजीकरण बढ़ जाएगा। लेकिन यह वायरस पर लगाम कसे जाने पर निर्भर होगा।

- कोरोनावायरस के प्रसार और ऊंचे करों से इस साल बाजार धारणा प्रभावित हो सकती है
- कंज्यूमर अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वर्ष 2020 में 95,200 करोड़ रुपये के अनुमान से नीचे रह सकता है
- 2019 में इस बाजार ने 85,300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ था, जो 2018 के मुकाबले 12 प्रतिशत ज्यादा है
- 16,300 करोड़ रुपये का एसी बाजार भी 2020 में 18,700 करोड़ रुपये के अनुमान से नीचे रह सकता है

अनुसार, हालांकि उनकी कंपनी चीन से आपूर्ति दबाव को झेलने में काफी हद तक सक्षम है, क्योंकि उसका निर्माण आधार इंडोनेशिया में है, लेकिन कोविड-19 महामारी का प्रभाव अल्पावधि में दिख सकता है। उन्होंने कहा, ‘इस महामारी का आने वाले महीनों में संपूर्ण व्यावसायिक परिवेश पर प्रभाव पड़ेगा।’

ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी त्यागराजन ने कहा कि इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि इस साल एसी बाजार पर इन कारकों का कितना प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘यदि चीन इस महामारी को नियंत्रित करने में विफल रहता है

वहीं इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को आगे बढ़ाए जाने से भी इस क्षेत्र में उपभोक्ता धारणा बुरी तरह से प्रभावित हुई है।’

इस क्षेत्र के विश्लेषकों का कहना है कि बिक्री पर दबाव पहली बार नहीं देखा गया है। इस क्षेत्र की कंपनियों को जीएसटी के संदर्भ में ऊंचे कराधान और कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की वजह से 2017 और 2018 में लगातार दो वर्षों तक बिक्री बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन पिछले साल एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और वाशिंग मशीन जैसी कई प्रमुख श्रेणियों में बिक्री में दो अंक तक का इजाफा दर्ज किया गया।

मार्च तिमाही में विप्रो पर नहीं पड़ेगा कोरोना संबंधी असर

बीएस संवाददाता

मुंबई, 17 मार्च

आईटी सेवा कंपनी विप्रो के मार्च तिमाही के प्रदर्शन पर विश्वव्यापी महामारी कोरोनावायरस का असर शायद नहीं पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्वोरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में कंपनी के राजस्व की रफ्तार 0–2 फीसदी के अनुमानित दायरे में रहेगी क्योंकि मौजूदा कारोबार से जुड़ा खाताबही अप्रभावित रहने की संभावना है।

हालांकि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में सुस्ती देखने को मिल सकती है क्योंकि क्लाइंटों की तरफ से खर्च में नरमी के कारण नए कारोबार पर प्रभाव पड़ने का पूर्व अनुमान है, जो राजस्व में बढ़ोतरी करता। रिपोर्ट में कहा गया है, हमें लग रहा है कि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के लिए राजस्व का अनुमान संभावित तौर पर –2 से 0 फीसदी के दायरे में रह सकता है क्योंकि कोरोनावायरस का असर बढ़ेगा, जो सीजन के लिहाज से हालांकि कंपनी के लिए सबसे सुस्त तिमाही होता है।

मंदी या अनिश्चित कारोबारी माहौल के दौरान क्लाइंटों की तरफ से खर्च मोटे तौर पर कम होता है क्योंकि ऐसे खर्च मोटे तौर पर क्लाइंटों के स्वविवेक पर निर्भर होते हैं। लेकिन ऐसे खर्च सामान्यतः कायापलट वाली बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, विप्रो के प्रमुख कारोबारी क्षेत्र मसलन विनिर्माण व संचार समेत अन्य क्षेत्र ने बढ़त की झलक दिखाई है। खास तौर से संचार क्षेत्र की रफ्तार बेहतर रही है क्योंकि देसी कारोबार से काफी कम

कंपनी समाचार 3

जी एंटरटेनमेंट का शेयर 20 फीसदी टूटा

विवेक सुजन पिंठो

मुंबई, 17 मार्च

जी एंटरटेनमेंट का शेयर मंगलवार को 20 फीसदी टूट गया। यह उस घटनाक्रम के एक दिन बाद हुआ जब एस्सेल समूह के प्रवर्तक सुभाष चंद्रा को येस बैंक की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा। चंद्रा बुधवार को ईडी के अधिकारियों से मिलेंगे, जिसकी पुष्टि एस्सेल समूह ने की।

मंगलवार को जारी बयान में जी ने स्पष्ट किया कि उसने येस बैंक से कोई उधारी नहीं ली है। जी ने कहा, एस्सेल समूह की सूचना के मुताबिक उधारी की सुविधा इन्फ्रा कारोबार के लिए ली गई थी, जो पूरी तरह सुरक्षित है। मीडिया कंपनी का शेयर बीएसई पर 133.20 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो सात साल का निचला स्तर है। बीएसई पर यह लगातार चौथे कारोबारी सत्र में टूटा।

कैलेंडर वर्ष 2020 में जी का शेयर 50 फीसदी से ज्यादा टूटा है जबकि साल के शुरू में यह 292 रुपये के स्तर पर था। यह इस अवधि में बेंचमार्क संसेक्स में 23 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

चंद्रा के अलावा जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, कॉक्स एंड किंग्स के प्रवर्तक पीटर केरकर, दीवान हाउसिंग के कपिल वधावन और कुछ अन्य को येस बैंक की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है।

कहा जाता है कि एस्सेल समूह की 16 कंपनियों ने संयुक्त रूप से येस बैंक से 8,415 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। इसमें से कुछ कर्ज एनपीए हो गए।

मनीष बने एफ्फेसिस के सीएफओ : सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एफ्फेसिस ने मनीष डुगर को मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाने की मंगलवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा कि यह नियुक्ति 15 मई से प्रभावी होगी। वी. सूर्यनायणन 14 मई तक सीएफओ पद पर बने रहेंगे। वह अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्त होने तक डुगर को कार्यभार संभालने में मदद करेंगे। *भ्रष्टा*

आईटीसी के कर्मचारी घर से काम करेंगे

कंपनी ने कोरोनावायरस के फैलने के मद्देनजर महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली एनसीआर और बेंगलूरु में अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया

अभिषेक रक्षित

कोलकाता, 17 मार्च

सिगरेट से लेकर होटल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आईटीसी ने कोरोनावायरस प्रभावित क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनी इस परिस्थिति से निपटने के लिए जल्द से जल्द एक आपात योजना तैयार कर रही है।

आईटीसी के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘महाराष्ट्र एवं केरल के कुछ भागों में और दिल्ली एनसीआर एवं बेंगलूरु के कार्यालयों को जल्द से जल्द एक आपात योजना तैयार करने और उसे लागू करने की सलाह दी गई है जिसमें

घर से काम करने की व्यवस्था भी शामिल है।’ आईटीसी के कर्मचारियों की संख्या 27,000 से अधिक है। हालांकि कोलकाता में कंपनी के मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर आ रहे हैं लेकिन कार्यालय परिसर से बाहर के लोगों को फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ‘आईटीसी के कर्मचारियों को छोड़कर किसी बाहरी आंगतुक को सुरक्षा कारणों से अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हरसंभव बढ़ावा दिया जा रहा है।’

कंपनी ने एक यात्रा परामर्श जारी किया गया है जिसके तहत कंपनी

^[1] आईटीसी के कर्मचारी घर से काम करेंगे

^[2] आईटीसी के कर्मचारी घर से काम करेंगे

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 13 अंक 26

नियामकीय कमी

जब येस बैंक के कामकाज पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हाल के समय की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक से गुजरना होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को जमाकर्ताओं की चिंताओं का निराकरण करके और उनसे हड़बड़ी में पैसा नहीं निकालने का आग्रह करके अच्छा किया। येस बैंक के

प्रशासकों ने भी मंगलवार को जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त नकदी की व्यवस्था की जा सकती है। बैंक ने कहा कि उसकी सभी शाखाओं और एटीएम में जरूरत के मुताबिक नकदी मौजूद है। मंगलवार शाम छह बजे प्रतिबंध समाप्त होने के पहले ये घोषणाएँ राहत देने वाली हैं। इससे यह आशा

जगी है कि नियामक बैंक के जमाकर्ताओं में कुछ हद तक भरोसा बहाल करने में कामयाब रहा है।

परंतु आने वाले दिनों में बैंकिंग नियामक और सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नियामक ने हालात इतने खराब क्यों होने दिए कि सामान्य बैंकिंग गतिविधियों को स्थगित करना पड़ा, जमाकर्ताओं को भारी असुविधा हुई और बैंक को संकट से उबारना पड़ा। येस बैंक दरअसल एक ऐसी दुर्घटना थी जिसे घटित होना ही था। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2014 से 2019 के बीच बैंक के अग्रिम की वार्षिक समेकित वृद्धि दर 34.1 फीसदी रही। जबकि इस अवधि में जमा 25.1 फीसदी की दर से बढ़ा। ऐसे आक्रामक विस्तार पर पहले ही ध्यान दिया

जाना चाहिए था। नियामक यह आंकने में भी नाकाम रहा कि बैंक के पास किस तरह की परिसंपत्तियाँ हैं। परिणामस्वरूप दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ 19 फीसदी की दर से बढ़ीं। बैंक जितनी तेजी से जमा गंवा रहा था उसे देखते हुए बहुत पहले ही चेतावनी मिल जानी चाहिए थी। 5 मार्च तक छह महीने में बैंक का जमा 35 फीसदी गिरा। समस्या दरअसल 2015-16 में ही शुरू हो गई थी जब आरबीआई ने परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा का आदेश दिया था। इसके कारण वित्त वर्ष 2016, 2018 और 2019 में कई गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का झुकाव येस बैंक के बहीखातों में हुआ और इसके अंकेक्षकों की नजर में आने का जोखिम उत्पन्न हो गया।

बड़ा मुद्दा यह है कि बैंकिंग नियामक जमाकर्ताओं और निवेशकों को किस प्रकार आश्वस्त करता है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। यह अहम है राज्य सरकार जैसे जमाकर्ता निजी बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। आरबीआई ने राज्य सरकारों को लिखा है और केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करके राज्यों से कहना चाहिए कि वे अनावश्यक निकासी न करें। यदि राज्य और सरकारी कंपनियाँ निजी बैंकों से पैसा निकालेंगे तो आम जमाकर्ता बचराएंगे। दूसरा विषय है येस बैंक का पुनर्गठन और इसके बचाव के लिए तथाकथित निजी-सार्वजनिक भागीदारी का। यह दिलचस्प है कि निजी बैंक के कई बैंक येस बैंक में इन्वेंट्री पूंजी निवेश के लिए आगे आए। इन बैंकों के अंशधारक यकीनन इस विचार से नाखुश हैं

और यह बात शेयर कीमतों से जाहिर भी हो रही है। संभव है कि येस बैंक को और अधिक पूंजी तथा इन बैंकों से निवेश की आवश्यकता हो। इसका असर इन बैंकों के अंशधारक प्रभावित होंगे और जोखिम में इजाफा होगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि नए निवेशकों के लिए शेयर कीमत कैसे तय हुई। कम कीमत से मौजूदा अंशधारक और कम होते और नए निवेशकों के लिए जोखिम कम होता। इसके अलावा शेयर धारकों के 100 से अधिक शेयर रखने पर प्रतिबंध भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेगा और बैंक के लिए पूंजी जुटाना और मुश्किल होगा। इनमें से कुछ मसलों को जितना जल्दी हल किया जाए बेहतर होगा। इससे भरोसा बहाल करने में सहायता मिलेगी।



अजय मोहन

इस समय कैसा देश का मंदड़िया बाजार ?

भारतीय बाजार शुक्रवार को खुलते ही लोअर सर्किट को छू गए, जिससे 45 मिनट तक कारोबार रोकना पड़ा। क्या बाजार जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं ? विस्तार से बता रहे हैं देवाशिष बसु

सेंसेक्स 13 फरवरी को 41,709 का स्तर छू गया था और विदेशी तथा घरेलू निवेश की लगातार आवक की बदौलत इसके और ऊंचाई पर जाने के आसार जताए जा रहे थे। साफ तौर पर संस्थागत निवेशकों, बाजार के जानकारों और निस्संदेह खुदरा निवेशकों में कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लगता है कि आर्थिक वृद्धि घटक 2.5 फीसदी पर आना कोई मुद्दा नहीं होगा। हां, पुरानी सीरीज के अनुसार वृद्धि 2.5 फीसदी होगी। हालांकि यह नई सीरीज के हिसाब से 4.5 फीसदी है।

बाजार से जुड़े लोग अब भी राजनीतिक नेतृत्व को दूरदृष्ट मानते हैं। राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान आर्थिक विकास के बजाय सामाजिक इंजीनियरिंग पर ज्यादा है। लेकिन यह भी अप्रासंगिक नजर आता है। ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड बेरोजगारी भी कोई मायने नहीं रखती है। वाहन, पूंजीगत माल, निर्यात, कपड़े जैसे क्षेत्रों में एक के बाद एक की वृद्धि में गिरावट को अस्थायी माना जा रहा है। बजट का उत्साहवर्धक न होना और उसके बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट ऐसी वजह थी, जिनसे बिकवाली नहीं बल्कि लिवाली होनी थी। विश्लेषकों के मुताबिक बाजार सस्ता है, जो वित्त वर्ष 2021 में आमदनी में भारी वृद्धि के काल्पनिक आंकड़ों पर आधारित

है। लेकिन यह भी गौर करें कि विश्लेषकों के बीच आमदनी के आंकड़ों को लेकर बनी सहमति कभी सही साबित नहीं हुई है। इसके बाद कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ा और ये अनुकूल परिस्थितियाँ बिगड़ गईं। पिछले शुक्रवार को भारतीय बाजारों में भारी गिरावट आई और ये लोअर सर्किट ब्रेकर को छू गए क्योंकि भय ने दुनियाभर में बाजारों को जकड़ लिया। संसेक्स 13 फरवरी को अपनी ऊंचाई से 13 मार्च को सूचकांक के निचले स्तर के बीच 29.5 फीसदी गिर चुका है। यह बहुत से लोगों के लिए आश्चर्यजनक है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं। संसेक्स 11 मई, 2006 को दैनिक कारोबार के दौरान 12,671 के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचा था, जो उसी साल 14 जून को दैनिक कारोबार के दौरान 8,799 तक लुढ़क गया। यह एक महीने में 30 फीसदी गिरावट थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाजार के पुराने खिलाड़ियों को भी एक महीने में 30 फीसदी गिरावट याद नहीं होगी, इसके कारणों को तो छोड़ ही दीजिए।

इस बार शेयर बाजारों के साथ कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है। वित्तीय विश्लेषकों ने तत्काल एक सुर में कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को अत्यधिक फायदा मिलेगा। यह तर्क दो

वजह से गलत है। पहला, सरकार तेल की कीमतों में गिरावट के मौके का इस्तेमाल कर बढ़ाने में करेगी। यह लाभ मुश्किल से ही कभी ग्राहकों तक पहुंचने दिया जाता है। मोदी सरकार ने ऐसा वर्ष 2015, वर्ष 2018 और इस बार फिर किया है। दूसरा, तेल की कीमतों में गिरावट का भारत को फायदा मिलने की बात कहना चयनित और स्वहित का तर्क है क्योंकि इसमें सिकके के एक पहलू को ही ध्यान में रखा गया है। तेल की कीमतों में गिरावट वैश्विक आर्थिक वृद्धि में गिरावट और मांग में मंदी की चिंताओं की वजह से आई है।

निश्चित रूप से आप तेल की कीमतों में गिरावट को एक सकारात्मक पहलू के रूप में नहीं देख सकते। आपको यह तथ्य पहचानना होगा कि मांग घटने के कारण बहुत से कारोबार बंद हो सकते हैं और बहुत से अत्यधिक प्रभावित हो सकते हैं। जब तक मांग बनी रहती है तो कारोबारी जगत लागत की परवाह नहीं करता है। अगर मांग घट जाती है तो इनपुट लागत घटने भी अप्रासंगिक हो जाता है।

असल मुद्दा यह है कि क्या कोरोनावायरस का संक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा। एक के बाद एक शहर और देश खुद को दूसरों से काट रहे हैं। स्कूल, कॉलेज,

सैर-सपाटे एवं मनोरंजन के केंद्र बंद हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रद्द की जा रही हैं और वैश्विक यात्रा कारोबार चरमरा चुका है। इस समय इस महामारी पर वैश्विक अंकुश लगाना जरूरी है, लेकिन इससे आपस में जुड़ी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक साथ व्यापार, परिवहन और पर्यटन में भी गिरावट आएगी। इससे मंदी आना सुनिश्चित है।

अमेरिका की सरकार ने ब्याज दरों एवं करों में कटौती और मौद्रिक नीति को नरम बनाकर इस दबाव को कम करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसे समय राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का क्या लाभ है, जब ज्यादा कारोबार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है और अडचनों जैसी स्थितियाँ बनाई जा रही हैं ?

क्या बाजार जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं ? शुक्रवार को भारतीय बाजार खुलते ही लोअर सर्किट को छू गए और 45 मिनट कारोबार को रोकना पड़ा। उनके फिर से खुलने से पहले यूएस इंडेक्स फ्यूचर्स सरकार की कुछ थोथी सरकारी घोषणाओं से चढ़ गए, जिसका वैश्विक बाजारों पर सकारात्मक असर पड़ा। इस वजह से भारतीय बाजार भारी तेजी के साथ खुले। यह द्विध्रुवीय बाजार की तरह नजर आ रहा है, जिसमें यह एक घंटे गिरता है और दूसरे घंटे चढ़ जाता है। यह अज्ञात चीजों के बारे में जानते हुए भी मानवीय प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। हम जानते हैं कि यह महामारी हम सभी को प्रभावित करेगी, लेकिन यह नहीं जानते कि किस हद तक करेगी। जब हम सोचते हैं कि यह हमें अत्यधिक प्रभावित (भय) करेगी तो हम भयभीत होकर बिकवाली करते हैं और जब हम यह मानते हैं कि इस पर काबू पा लिया जाएगा (उम्मीद) तो हमें खरीद के मौके नजर आते हैं। लोगों को अनिश्चितता से घृणा है और उनकी इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया होती है। जितनी अधिक अनिश्चितता होती है, उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही कड़ी होती है।

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक तीन तरह के मंदड़िए बाजार होते हैं। इनमें से एक युद्ध, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी या उभरते बाजारों के संकट जैसे विशेष घटनाक्रम से संचालित होता है। ये घटनाएं भारत में नोटबंदी या अमेरिका में 9/11 जैसी घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा बाजार चक्रीय होता है, जिसका कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी, मंदी की आशंका और लाभ में गिरावट जैसे कारकों के चलते आर्थिक चक्र में बदलाव होता है। इस तरह का मंदड़िया बाजार सूचकांक के मूल्य को 30 फीसदी घटा सकता है। ऐसा पहले ही हो चुका है। तीसरा ढांचागत मंदड़िया बाजार होता है, जो अर्थव्यवस्था में भारी असंतुलन और वित्तीय बुलबुलों की वजह से पैदा होता है। इसके बाद आम तौर पर कीमतों में बढ़ोतरी और अवस्फीति आती है। ऐसे मंदड़िए बाजारों में गिरावट करीब 57 फीसदी है। सवाल पैदा होता है कि इस समय कौनसा मंदड़िया बाजार है ? मेरा अनुमान है कि संस्थागत निवेशक यह मानते हैं कि यह घटना प्रेरित या चक्रीय है। लेकिन हकीकत यह है कि हम नहीं जानते। अगर महामारी को एक या दो महीनों में नियंत्रित कर लिया गया तो हमारे पास लिवाली के भारी मौके होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम गंभीर आर्थिक संकट के कगार पर खड़े हैं, जिसके आकार-प्रकार से हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।

वृद्धि के अनुमान जल्द आने और कम होने से बढ़ेगा भरोसा

जब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी 2017 में वर्ष 2016-17 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर संबंधी अनुमानों की घोषणा की थी तो नरेंद्र मोदी सरकार के आर्थिक नीति-निर्माताओं में निराशा देखी गई थी। जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान था जो सरकार की अपेक्षाओं से काफी कम और 2015-16 की वृद्धि दर से भी कम थी। आलोचकों ने कहा था कि यह आंकड़ा नोटबंदी के दुष्परिणामों का शुरुआती संकेत है। नोटबंदी के दौरान चलन में मौजूद 86 फीसदी बड़े नोटों को निरस्त घोषित कर दिया गया था। इस वजह से अर्थव्यवस्था को गहरे आघात का सामना करना पड़ा था और आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की आशंकाएं बढ़ने लगी थीं।

लेकिन वर्ष 2016-17 में देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर बनी धारणा दो साल बाद पूरी तरह बदल गई। उस वर्ष के लिए वृद्धि दर को संशोधित कर 8.2 फीसदी कर दिया गया। इस वृद्धि दर को संशोधित कर 8.2 फीसदी कर दिया गया। इसके बाद सरकार के आर्थिक नीति-निर्माता जोर-शोर से कहने लगे कि नोटबंदी के साल में भी वृद्धि दर न केवल मजबूत बनी रही बल्कि एक साल पहले की आठ फीसदी की वृद्धि दर से ऊंची भी रही। वर्ष 2016-17 के बारे में आए एक अन्य संशोधित अनुमान में वृद्धि दर को 8.3 फीसदी कर दिया गया।

दरअसल यह भारत में आर्थिक आंकड़ों में बार-बार किए जाने वाले संशोधनों का नतीजा है। सीएसओ किसी भी वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि के बारे में कुल छह अनुमान जारी करता है। एक ही वित्त वर्ष के बारे में ये वृद्धि अनुमान तीन साल के दौरान जारी किए जाते हैं।

इस तरह वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि के बारे में पहले अग्रिम अनुमान जनवरी 2017 में जारी किए गए। दूसरा अग्रिम अनुमान इसके एक महीने बाद फरवरी 2017 के आखिर में जारी किया गया। अस्थायी अनुमान कहे जाने वाले तीसरे अनुमान मई 2017 में जारी किए गए। फिर आठ महीनों के लंबे अंतराल पर प्रथम संशोधित अनुमान के रूप में चौथा अनुमान जनवरी 2018 में जारी किया गया। वर्ष 2016-17 की आर्थिक वृद्धि के बारे में



दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

दो अन्य अनुमान भी एक-एक साल के अंतराल पर जारी हुए। दूसरा संशोधित अनुमान 31 जनवरी, 2019 को आया जबकि तीसरा संशोधित अनुमान उसके ठीक एक साल बाद 31 जनवरी, 2020 को जारी किया गया।

वर्ष 2016-17 में जीडीपी संबंधी शुरुआती चार अनुमानों में कोई बदलाव नहीं किया गया था और इनमें वृद्धि दर 7.1 फीसदी पर ही थी। लेकिन दूसरे संशोधित अनुमान में इस दर को 8.2 फीसदी कर दिया गया और तीसरे संशोधित अनुमान में यह 8.3 फीसदी कर दी गई।

जीडीपी वृद्धि अनुमानों में बड़े फेरबदल का यह सिलसिला वर्ष 2017-18 और 2018-19 में भी थोड़े-बहुत बदलावों के साथ जारी रहा। वर्ष 2017-18 के लिए पहला अग्रिम अनुमान 6.5 फीसदी वृद्धि का था जिसे दूसरे अग्रिम अनुमान में बढ़ाकर 6.6 फीसदी कर दिया गया। अस्थायी अनुमान में इसे फिर से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया।

जनवरी 2019 में जारी पहले संशोधित अनुमान में यह 7.2 फीसदी और उसके एक साल बाद जारी दूसरे संशोधित अनुमान में हल्की गिरावट के साथ सात फीसदी कर दी गई। तीसरा संशोधित अनुमान आगले साल जनवरी में जारी किया जाएगा और तब संभवतः एक और नया आंकड़ा सामने आएगा।

जहां तक वर्ष 2018-19 का सवाल है तो अभी तक इसके बारे में पहले चार अनुमान ही सामने आए हैं लेकिन इन सभी में चार अलग-अलग आंकड़े देखे गए हैं। जनवरी 2019 में जारी पहले अग्रिम अनुमान में वृद्धि दर 7.2 फीसदी बताई गई थी जो फरवरी 2019 में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में सात फीसदी, मई 2019 में 6.8 फीसदी और

जनवरी 2020 में संशोधित कर 6.1 फीसदी कर दी गई। इसके पहले के दो वित्त वर्षों के उलट 2018-19 के बीच अनुमानों में वृद्धि दर लगातार नीचे की ओर संशोधित की गई है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के बारे में पहले दो अनुमान सामने आ चुके हैं जिनमें बिना किसी बदलाव के वृद्धि दर पांच फीसदी रहने की बात कही गई है।

सकल मूल्य-वर्द्धन, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल निर्धारित पूंजी सृजन जैसे अन्य मानकों में भी आंकड़े बदलते रहे हैं।

आर्थिक वृद्धि के आंकड़े अर्थव्यवस्था की हालत जांचने और जरूरी उपाय सुझाने के लिए नीति-निर्माताओं के पास एक अहम साधन है। अगर ये आंकड़े इतना बदलते रहते हैं तो इससे किसी भी नीतिगत पहल की प्रभावोत्पादकता प्रभावित होगी। करीब तीन साल की लंबी अवधि में इसे अंजाम दिए जाने का भी असर पड़ता है। इन छह अनुमानों में से जब भी कोई फेरबदल होता है तो उसके अगले साल के अनुमानों में भी संशोधन होना जरूरी हो जाएगा।

सीएसओ हर बार यह बताता है कि नए अनुमान में फेरबदल हुआ है। लेकिन इससे नीति-निर्माताओं की चुनौतियाँ कम नहीं हो जाती हैं। ऐसे बदलते आंकड़ा जारी करने वाली व्यवस्था को राजनीतिक दबाव के लिहाज से असुरक्षित बना देता है ताकि एक खास राजनीतिक धारणा को पसंद आने वाले आंकड़े ही पेश किए जाएं। सीएसओ को तमाम अनुमानों तक पहुंचने की कार्य-पद्धति पर गौर करने के साथ ही व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए जरूरी उपचारात्मक कदमों का परीक्षण भी करना चाहिए। इसके साथ सीएसओ को एक ही वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि के बारे में तीन वर्षों के भीतर छह अलग अनुमान जारी करने के बजाय एक ही परखना चाहिए। साफ तौर पर वृद्धि अनुमान जारी करने की मियाद और उनकी संख्या में कटौती करने से आंकड़ों की विश्वसनीयता और राजनीतिक दबावों के प्रति उनकी असुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी दूर की जा सकेंगी।

कानाफूसी

घर पर मध्याह्न भोजन

क्या आपने कभी सोचा है कि जिन दिनों विद्यालय बंद रहते हैं उन दिनों मध्याह्न भोजन योजना का क्या होता है ? केरल की सरकार इस मामले में एक नया उदाहरण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए कक्षा-7 तक के सभी स्कूल फिलहाल बंद कर दिए हैं। परंतु केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी के सभी बच्चों को उनके घर पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों की संख्या और आंगनबाड़ी से उनके घर की दूरी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उन्हें पका-पकाया भोजन भिजवाया जाए या कच्चा अनाज दिया जाए। अगले कुछ दिनों तक हर बच्चे को 255 ग्राम दाल, 120 ग्राम गेहूं, 170 ग्राम मूंगफली, 55 ग्राम तेल और 180 ग्राम गुड़ दिया जाएगा। इसकी मदद से आसानी से पायसम (खीर) बनाई जा सकती है। आमतौर पर बच्चों को सप्ताह में दो दिन पायसम खिलाया जाता है। प्रदेश की 33,115 आंगनबाड़ियों में 375,000 बच्चे मध्याह्न भोजन योजना का लाभ लेते रहे हैं।



आपका पक्ष

पेट्रोल पर शुल्क वृद्धि से बढ़ेगा राजस्व

कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण दुनिया भर में व्यापार के क्षेत्र में उथल-पुथल मची है। चीन जैसे बड़े उपभोक्ता देश में पेट्रोलियम के इस्तेमाल में कमी आई है। विभिन्न कारणों से कच्चे तेल के दाम में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले कई दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी कमी आई है। हालांकि, सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की। इससे सरकार को 39,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर से नीचे जा चुकी है। अब सरकार को इसे 70 रुपये के आसपास बनाए रखने के लिए यदि संभव हो तो फिर से उत्पाद शुल्क में वृद्धि करनी चाहिए। इससे एक ओर जहां पेट्रोलियम उत्पाद के बेजा इस्तेमाल पर लगाम लगेगी वहीं सरकारी खजाने में भी पैसा बढ़ेगा। इस



अतिरिक्त रकम का इस्तेमाल सरकार प्रदूषण को कम करने के उपायों पर खर्च कर सकती है। मसलन पौधरोपण का अभियान चलाने, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने आदि के लिए। पराली जलाने वाले किसानों को भी रोकने के लिए आर्थिक प्रावधान किया जा सकता है।

सौरभ पासवान, मुजफ्फरपुर

हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर का इजाजा किया गया है

मुक्तिधामों का हो जीर्णोद्धार

दिवंगत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया के लिए स्थापित मुक्तिधामों में व्यास गंदगी और

अव्यवस्था वर्षों से गंभीर चिंता का विषय रही है। वर्तमान में रमशान घाटों पर गंदगी बढ़ती जा रही है। अंतिम संस्कार के लिए गए लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इनमें प्रमुख समस्या मुक्तिधाम के परिसर में व्यास गंदगी है। अंतिम संस्कार में आए परिवर्जन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते पाए जाते हैं। परिवर्जन मृत व्यक्ति के कपड़े, बर्तन सहित दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं मुक्तिधाम परिसर में ही छोड़ जाते हैं। कुछ लोग लंबी बीमारी के बाद मरने वाले व्यक्ति का मेडिकल वेस्ट जैसे ग्लूकोज बोतल का ट्यूब, इन्सुलिन की सिरिंज, बची हुई दवाइयाँ आदि भी शववाह स्थल के आसपास ही फेंक देते हैं। दरअसल यह सब अत्यधिक अप्रिय परिवर्जनों की लापरवाही से ही हो रहा है। स्वच्छता के प्रति उनकी सोच और मानसिकता में कमी का

ही परिणाम है कि बेहद गमगीन माहौल के बीच साफ-सफाई को लेकर जरा भी जागरूकता नहीं दिखाते। चिंता से बची अधजली लकड़ियाँ, राख, अर्थियों के अवशेष भी यहाँ-वहाँ पड़े दिख जाते हैं। समुचित अस्थातें और चौकीदार की अनुपस्थिति में कई बार अत्येष्टि स्थल असामाजिक तत्वों का आश्रय स्थल बन जाते हैं। देखा गया है कि अत्येष्टि स्थलों के प्रबंधन में बड़े स्तर पर लापरवाही बरती जाती है। साथ ही सौंदर्यकरण के कार्य केवल कागजों में ही दिखा दिए जाते हैं। एक आदर्श अत्येष्टि स्थल में अहाता युक्त प्रांगण होने के साथ-साथ परिवर्जनों के लिए पानी और छाँव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मुक्तिधामों में 24 घंटे चौकीदारों को तैनाती होनी चाहिए। परिसर की सफाई की भी समुचित व्यवस्था होने चाहिए और अंतिम संस्कार के लिए आए परिवर्जन आदि को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

रूपेश देव पाण्डेय पामगढ़, छत्तीसगढ़

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

धातुओं में गिरावट का दौर जारी

कोरोनावायरस की चिंता के कारण मूल धातुओं और कीमती धातुओं में बना हुआ है नरमी का रुख

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 17 मार्च

कोरोनावयरस (कोविड -19) का प्रकोप अन्य देशों में फैलने और इसके नए मामले सामने आने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की चिंताओं के कारण पिछले दिन की तीव्र गिरावट के उपरांत अस्थिरता के बीच मंगलवार को भी जिंस के दामों में गिरावट जारी रही है। एमसीएक्स पर मूल धातुओं और कीमती धातुओं के वायदा में गिरावट आई है। एलएमई पर भी धातुओं की कीमतों में गिरावट रही।

जबेरी बाजार में मंगलवार को चांदी चार प्रतिशत तक गिरकर 35,145 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जबकि सोमवार यह 36,640 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। लेकिन व्यापारी सौदे करने को तय्युक नहीं थे और वे खरीदारों को लागत के मुकाबले ज्यादा दामों की पेशकश कर रहे थे। ऐसे में थोक दामों पर कम ही सौदे हुए। कई डीलरों ने काफी कम दामों पर अप्रैल डिलिवरी की पेशकश की। वर्ष 2020 में अब तक चांदी के हाजिर दामों में 24.7 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, जबकि सोना अपनी पूरी बढ़त गंवाकर केवल 1.6 फीसदी बढ़त के स्तर पर रह गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया



(एमसीएक्स) पर अप्रैल में डिलिवरी वाले सोने का वायदा भाव दोपहर बाद के कारोबार में 1.96 प्रतिशत तक टूटकर 38,743 रुपये रह गया था। मई डिलिवरी के लिए चांदी के वायदा भाव में 4.8 प्रतिशत की तेज गिरावट आई और यह 34,470 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इस साल जनवरी के दौरान चीन में जब पहली बार कोविड-19 की सूचना मिली थी, तब सोने और चांदी में क्रमशः 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक की गिरावट आ चुकी है। वर्ष 2020 में एमसीएक्स पर चांदी 3.2 प्रतिशत और सोना 1.5 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

कोटक सिन्क्योरिटीज की सहायक उपाध्यक्ष प्रियंका झावेरी ने कहा कि कोविड-

19 के बढ़ते प्रसार और इसकी मार के कारण इक्विटी और जिंसों की वैश्विक धारणा लगातार कमजोर बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप जिंसों में गिरावट के रुख के साथ अस्थिरता जारी रहेगी।

वैश्विक शेरों में गिरावट आनी शुरू होने के बाद हाजिर और वायदा दोनों सकारात्मक संकेत के साथ खुले थे, लेकिन दोपहर के सत्र में इनमें गिरावट आ गई जो वायदा में दिन के सत्र के कारोबार के समाप्त होने तक जारी रही। मोतीलाल ओम्बवाल फार्मेशनल सर्विसेज लिमिटेड के एसोसिएट निदेशक किशोर नरणे ने कहा कि स्टॉक में मार्जिन का भुगतान करने के लिए कारोबारियों ने सोने और चांदी जैसे विविधतापूर्ण परिसंपत्ति

नरम पड़ती धातु

■ एमसीएक्स पर मूल धातुओं और कीमती धातुओं के वायदा में गिरावट आई, एलएमई पर भी धातुओं में गिरावट रही

■ जबेरी बाजार में चांदी 4 प्रतिशत तक गिरकर 35,145 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जबकि सोमवार को यह 36,640 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी

वर्षों में अपनी होल्डिंग बेची है।

इस बीच सोने और चांदी में अस्थिरता से कल एमसीएक्स पर सराफा में रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार हुआ। सराफा खंड में 35,112.36 करोड़ रुपये का कुल कारोबार हुआ। दूसरी ओर, मंगलवार को लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर निकल को छोड़कर सभी प्रमुख धातुओं में एक से डेढ़ प्रतिशत के बीच गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों को कोविड-15 के द्वितीय स्तर (संक्रमण के 100 से अधिक मामलों) का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों ने इसका प्रसार रोकने के लिए वस्तुओं और लोगों का देश में आना-जाना सीमित कर दिया है।

कोरोना से चीनी आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक दामों को झटका

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 17 मार्च

वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगातार मंदी की ओर ले जा रही विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 (कोरोनावायरस) का साया घरेलू चीनी आपूर्ति श्रृंखला पर भी दिखने लगा है। मिलों से होने वाली चीनी खरीद में पिछले एक पखवाड़े के दौरान गिरावट आई है। यहां तक कि चीनी के अंतरराष्ट्रीय दाम भी 15 डॉलर प्रति पाउंड से घटकर 12 डॉलर से नीचे जा चुके हैं।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के

अनुसार इस प्रकोप से पिछले 15 दिनों के दौरान मिलों से होने वाली चीनी बिक्री ठप हो गई है तथा माना जा रहा है कि थोक और खुदरा बाजारों में चीनी स्टॉक पिछले कुछेक सप्ताह में बिक चुका है। बाजार की समीक्षा करने वालों के अनुसार मिलों से चीनी की नई खरीद जल्द ही शुरू होगी क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला पिछले कुछेक सप्ताह के दौरान काफी हद तक कम हो चुकी होगी। इससे चीनी के दाम नियंत्रित रहेंगे, जबकि ताजा खरीद से घरेलू मिलों को मदद मिलेगी। इस्मा का कहना है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण मौजूदा 'अभूतपूर्व' स्थिति ने चीनी के

वैश्विक दामों को प्रभावित किया है। हालांकि यह प्रभाव अस्थायी हो सकता है। इंडोनेशिया में निर्यात के नए अवसरों के संकेत मिले हैं। इस्मा ने कहा कि थाईलैंड के चीनी उत्पादन में 50 लाख टन तक की कमी तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड से रियायती आयात शुल्क पर चीनी करने आयात की अनुमति देने के इंडोनेशिया के फैसले ने भारतीय कंपनियों को निर्यात के आकर्षक अवसर प्रदान किए हैं।

इसके अलावा इंडोनेशिया ने अपनी रिफाइनरियों के लिए अतिरिक्त आयात कोटा जारी किया है और इस बात को ध्यान में

रखते हुए कि थाईलैंड से चीनी की उपलब्धता में पहले ही 50 लाख टन की कमी आ चुकी है, भारत की कच्ची चीनी का इंडोनेशिया को निर्यात करने का अच्छा मौका मिला है। भारतीय मिलों 15 मार्च, 2020 तक 60 लाख टन की अधिकतम स्वीकृत निर्यात मात्रा (एमआईक्यू) के मुकाबले निर्यात के लगभग 38 लाख टन चीनी अनुबंधों में से करीब 30 लाख टन की खेप भेज चुकी हैं। मिलों द्वारा प्रमुख निर्यात या व्यापारिक निर्यातक के जरिये निर्यात के लिए इस एमएमईक्यू का निर्धारण केंद्र सरकार करती है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

| As on Mar 17 | International Price | %Chg* | Domestic Price | %Chg* |
|------------------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|
| METALS (\$/tonne) | | | | |
| Aluminium | 1,640.5 | -6.5 | 1,885.5 | -0.9 |
| Copper | 5,211.0 | -15.6 | 5,845.1 | -9.4 |
| Nickel | 11,775.0 | -16.4 | 12,188.6 | -16.8 |
| Lead | 1,685.0 | -10.0 | 1,912.5 | -14.1 |
| Tin | 15,400.0 | -10.5 | 16,161.6 | -10.4 |
| Zinc | 1,932.0 | -15.9 | 2,047.1 | -21.5 |
| Gold (\$/ounce) | 1,483.5* | 0.5 | 1,664.1 | 0.0 |
| Silver (\$/ounce) | 12.5* | -26.6 | 14.7 | -24.1 |
| ENERGY | | | | |
| Crude Oil (\$/bbl) | 28.3* | -58.2 | 30.6 | -54.0 |
| Natural Gas (\$/mmBtu) | 1.8* | -22.8 | 1.8 | -22.4 |
| AGRI COMMODITIES (\$/tonne) | | | | |
| Wheat | 179.8 | -5.4 | 270.3 | -10.2 |
| Maize | 178.9* | -3.4 | 219.4 | -24.6 |
| Sugar | 340.6* | -3.4 | 464.9 | -4.0 |
| Palm oil | 570.0 | -20.8 | 942.8 | -16.8 |
| Rubber | 1,433.3* | -10.7 | 1,737.4 | -6.6 |
| Coffee Robusta | 1,209.0* | -14.0 | 1,811.4 | -4.4 |
| Cocoa | 1,308.9 | -10.6 | 1,425.2 | -10.3 |

* As on Mar 17, 201800 hrs IST, % Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 74.38 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes: 1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat UFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural Gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Maize & Maize are NCDER future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are in near month contract. 6) International Wheat & Maize are NCDER future prices of near month contract, Palm oil & Rubber and Prices of Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDER future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDER spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton 11-NY01 near month future & domestic cotton is MCX future prices near month futures.

Bloomberg chartMaker

Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|----------------------------|-------------|---------|
| Agri commodity | | |
| Cotton | 68.7 | 40874 |
| Oil and Oilseeds | 420.6 | 93274 |
| Spices | 0.4 | 8 |
| Metal(Mar 16) | | |
| Metal- non ferrous | 69142 | 36543 |
| Metal- precious | 35112.4 | 361 |
| Oil and gas(Mar 16) | | |
| Gas | 2398.2 | 22575 |
| Oil | 86142 | 2018 |

औद्योगिक

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|-----------------------------|-------------|---------|
| Metals | | |
| Aluminium utensil scrap /kg | 107 | (107) |
| Aluminium ingots /kg | 140 | (140) |
| Brass sheet cutting /kg | 319 | (310) |
| Brass utensil scrap/kg | 295 | (290) |
| Copper heavy scrap /kg | 402 | (409) |
| Copper utensil scrap/kg | 375 | (378) |
| Copper wire bar /kg | 434 | (441) |
| Lead ingots /kg | 142 | (144) |
| Nickel Cathodes /kg | 905 | (930) |
| Ti slabs /kg | 1200 | (1225) |
| Zinc slabs /kg | 152 | (158) |

Source: Bombay Metal Exchange

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Commodity | | |
| Chana-Bikaner NCDXE(1 Qtl) | 10348 | (10292) |
| Bengal Deshi /Qtl | 11023 | (11023) |
| DCh- 32 /Qtl | 9392 | (9392) |
| Jaychari /Qtl | 10826 | (10826) |
| Shankar- 6 /Qtl | | |
| Source: Cotton Association of India | | |
| Mumbai | | |
| Castor FSG /10kg | 818 | (830) |
| Castor Comm /10kg | 828 | (820) |
| Ricebran oil/10kg | 820 | () |

Source: Petroleum Bazaar.com

एनसीडीईएक्स

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|-------------------------|-------------|---------|
| Agri commodity | | |
| Cotton | 113.1 | 106691 |
| Grains | 158.8 | 70485 |
| Oil and Oilseeds | | |
| Others | 109.3 | 56300 |
| Pulses | | |
| Others | 63.9 | 46400 |
| Spices | | |
| Others | 35.1 | 18333 |

Source: India Bullion & Jewellers Association

सॉफ्ट

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|--|-------------|-------------|
| Sugar | | |
| Mumbai M-30 /Qtl | 3332-3572 | (3332-3572) |
| Source: Bombay Sugar Merchants Association | | |
| ऊर्जा | | |
| Crude Brent-5/Barrel | 29.17 | (28.7) |
| NYSE Crude | 28.35 | (27.93) |
| Brent Crude (WTI) | 28.7 | (28.3) |
| NYSE Natural Gas-\$/Mmbtu | 1.79 | (1.82) |
| Furnace/ 180 Cst &/hbl | 190.72 | (171.53) |
| Naphtha spot /M/T | 45170 | (45170) |
| LHS/ spot /M/T | 36150 | (36150) |
| Chana Bikaner /Qtl | 39590 | (33950) |
| Source: Petroleum Bazaar.com | | |

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

| Name (Maturity) | Close | Day* |
|-----------------------------|---------|-------|
| Gainers (* % Change) | | |
| Crude Palm Oil (Mar 31) | 612.7 | 0.8 |
| Cotton (Mar 31) | 17990.0 | 0.6 |
| Kapas (Apr 30) | 982.5 | 0.1 |
| Losers (* % Change) | | |
| Silver Mini (Apr 30) | 36252.0 | -10.6 |
| Silver (May 05) | 36207.0 | -10.6 |
| Crude Oil (Mar 19) | 2161.0 | -9.8 |
| Silver Micro (Apr 30) | 37011.0 | -9.2 |
| Nickel (Mar 31) | 8923.5 | -3.1 |
| Gold Petal (Mar 31) | 3902.0 | -3.0 |
| Natural Gas (Mar 26) | 136.4 | -2.4 |
| Zinc Mini (Mar 31) | 148.3 | -2.3 |
| Copper (Mar 31) | 412.5 | -2.2 |

Source: India Bullion & Jewellers Association

सर्साफा

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|---|-------------|---------|
| Gold | | |
| Pure (99.50 Purity) /10 gms | 39726 | (39835) |
| Pure (99.90 Purity) /10 gms | 39886 | (39995) |
| Silver-999 /kg | 35145 | (36640) |
| Source: India Bullion & Jewellers Association | | |

Source: India Bullion & Jewellers Association

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

| Name (Maturity) | Close | Day* |
|--------------------------------|---------|------|
| Gainers (* % Change) | | |
| Coriander-Kota (Apr 20) | 5620.0 | 1.4 |
| Turmeric Nizamabad (Mar 20) | 5416.0 | 1.3 |
| Soybean Indore (Mar 20) | 3374.0 | 1.3 |
| Chana-Bikaner (Mar 20) | 3975.0 | 1.2 |
| Jeera Unjha (Mar 20) | 13580.0 | 1.1 |
| Guar Gum 5 MT-Jodhpur (Mar 20) | 3440.0 | 1.1 |
| Ref Soy Oil-DR-2016 (Mar 20) | 752.2 | 0.9 |
| CottonSeed Oil-Akola (Mar 20) | 1786.0 | 0.9 |
| Mustard Seed Rape Oil (Apr 20) | 3868.0 | 0.8 |
| Losers (* % Change) | | |
| Crude Palm Oil-KAKIN (Mar 20) | 620.0 | -4.0 |
| MustardSeed Alwar (Mar 20) | 3642.0 | -2.8 |
| GuarGum 5T-Jodhpur (Mar 20) | 5274.0 | -1.7 |

Source: India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

| Commodity | Unit | Pclose | Price (₹) | Close |
|-------------------------|--------|----------|-----------|----------|
| 29 mm Cotton-Rajkot (N) | 1 B | 18402.10 | 18364.55 | 18402.10 |
| Alumini-Mumbai (M) | 1 K | 140.70 | 140.90 | 140.70 |
| Bajra-Delhi (N) | 1 Q | 1650.00 | 1618.75 | 1650.00 |
| Bajra-Jaipur (N) | 1 Q | 1640.00 | 1624.15 | 1640.00 |
| Barley-Jaipur (N) | 1 Q | 1737.00 | 1748.05 | 1737.00 |
| Basmati-Ambisar (I) | 100 KG | 3232.00 | 3258.00 | 3232.00 |
| Cardamom-Vand. (I) | 1 K | 2700.00 | 2683.00 | 2700.00 |
| Castor Seed-Oisa (N) | 1 Q | 3881.25 | 3871.85 | 3881.25 |
| Castor Seed-Kadi (N) | 1 K | 3850.00 | 3830.00 | 3850.00 |
| Chana-Bikaner (N) | 1 Q | 3922.20 | 3926.65 | 3922.20 |
| Chana-Delhi (N) | 1 Q | 4114.70 | 4145.00 | 4114.70 |
| Chana-Akola (N) | 1 K | 3831.25 | 3875.00 | 3831.25 |
| Contander-Gondal (N) | X | 5704.00 | 5732.00 | 5704.00 |

Source: India Bullion & Jewellers Association

कल का हाजिर भाव

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|-----------------------|-------------|---------|
| Crude Oil | | |
| Crude Oil (Mar 31) | 612.7 | 0.8 |
| Cotton (Mar 31) | 17990.0 | 0.6 |
| Kapas (Apr 30) | 982.5 | 0.1 |
| Losers | | |
| Silver Mini (Apr 30) | 36252.0 | -10.6 |
| Silver (May 05) | 36207.0 | -10.6 |
| Crude Oil (Mar 19) | 2161.0 | -9.8 |
| Silver Micro (Apr 30) | 37011.0 | -9.2 |
| Nickel (Mar 31) | 8923.5 | -3.1 |
| Gold Petal (Mar 31) | 3902.0 | -3.0 |
| Natural Gas (Mar 26) | 136.4 | -2.4 |
| Zinc Mini (Mar 31) | 148.3 | -2.3 |
| Copper (Mar 31) | 412.5 | -2.2 |

Source: India Bullion & Jewellers Association

कल का हाजिर भाव

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|-----------------------|-------------|---------|
| Crude Oil | | |
| Crude Oil (Mar 31) | 612.7 | 0.8 |
| Cotton (Mar 31) | 17990.0 | 0.6 |
| Kapas (Apr 30) | 982.5 | 0.1 |
| Losers | | |
| Silver Mini (Apr 30) | 36252.0 | -10.6 |
| Silver (May 05) | 36207.0 | -10.6 |
| Crude Oil (Mar 19) | 2161.0 | -9.8 |
| Silver Micro (Apr 30) | 37011.0 | -9.2 |
| Nickel (Mar 31) | 8923.5 | -3.1 |
| Gold Petal (Mar 31) | 3902.0 | -3.0 |
| Natural Gas (Mar 26) | 136.4 | -2.4 |
| Zinc Mini (Mar 31) | 148.3 | -2.3 |
| Copper (Mar 31) | 412.5 | -2.2 |

Source: India Bullion & Jewellers Association

कल का हाजिर भाव

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|--------------------|-------------|---------|
| Crude Oil | | |
| Crude Oil (Mar 31) | 612.7 | 0.8 |
| Cotton (Mar 31) | 17990.0 | 0.6 |
| Kapas (Apr 30) | 982.5 | 0.1 |
| Losers | | |

आयुष्मान में कोरोना का भी इलाज

सरकार की प्रमुख आयुष्मान योजना में बीमारी के रोकथाम के लिए कोई कवर नहीं था लेकिन अब इसके लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है

निवेदिता मुखर्जी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत कोरोनावायरस के लिए 'कोविड-19 विशेष पैकेज' की तैयारी में जुटा है क्योंकि कई राज्यों में संक्रमण के मामले में इजाफा हो रहा है। एनएचए के मुख्य कार्यकारी इंदु भूषण ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि प्राधिकरण एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रहा है जिनमें विशेष पैकेज देने जैसा कदम भी शामिल है। कोरोनावायरस के लिए अलग वार्ड बनाने के पैकेज की योजना बनाई जा रही है जिसकी समीक्षा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) करेगा। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का संचालक मंडल भी इसे मंजूरी देगा।

अधिकारियों ने कहा कि अगर कोरोनावायरस का प्रसार सामुदायिक स्तर तक फैलता है तब ऐसे पैकेज की जरूरत होगी। फिलहाल आयुष्मान-पीएमजेएवाई योजना में बीमारी के रोकथाम से जुड़ा स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं है बल्कि इसमें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होने और गंभीर बीमारियों के इलाज और सामान्य वॉर्ड के लिए बीमा कवर मुहैया कराया जाता है।



लेकिन इस योजना में अलग वॉर्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए अलग वॉर्ड की जरूरत होगी जिनका खर्च अधिक होगा और इस पर पीएमजेएवाई के तहत खर्च किया जाएगा। एनएचए ने संक्रमण के आंकड़े और कॉल सेंटर के ब्योरे पर भी नजर रखी है। भूषण का कहना है कि इन उपायों से देश में कोरोनावायरस के असर को कम करने में मदद मिलेगी। आयुष्मान के आंकड़ों पर निगरानी करने वाले अधिकारी इन्फ्लूएंजा

आयुष्मान केंद्रों पर कोरोना जांच की अनुमति देने के लिए बातचीत जारी

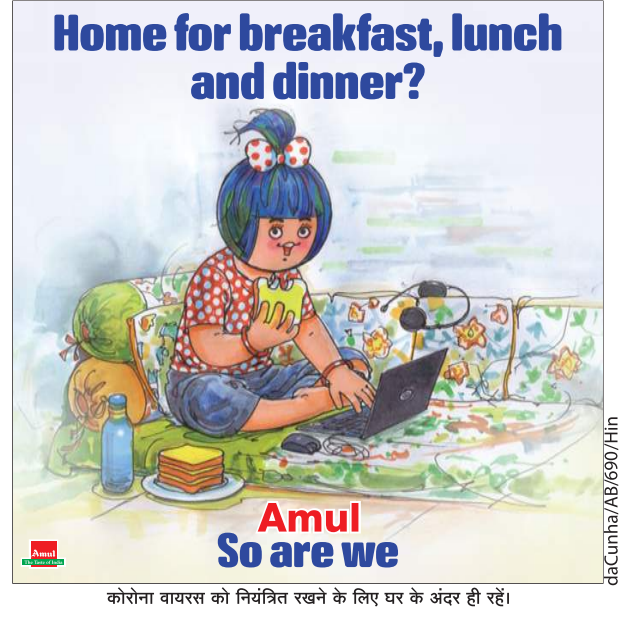
और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारी में बढ़ती पर नजर बनाए हुए हैं। अगर इनमें असामान्य इजाफा दिखता है तब इसकी जानकारी आईसीएमआर को दी जाएगी ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि बीमा पर्याप्त विश्लेषण के इस आंकड़े को साझा नहीं किया जाएगा। अधिकृत आयुष्मान केंद्रों पर कोरोनावायरस की जांच की अनुमति देने के लिए एनएचए और आईसीएमआर में बातचीत जारी है।

किफायती जांच पर जोर

पृष्ठ 1 का शेष

इस समय देश में 72 आईसीएमआर जांच घर मरीजों की जांच कर रहे हैं और इस सप्ताह के अंत तक 49 नए सरकारी लैब सक्रिय किए जाएंगे। इससे देश में कुल जांचघरों की संख्या बढ़कर 121 हो जाएंगी। आईसीएमआर के प्रमुख एवं स्वास्थ्य शोध विभाग (डीएचआर) में सचिव बलराम भार्गव ने कहा कि उनसे कई निजी जांचघरों ने संपर्क कर इस संकट के घड़ों में सहयोग देने की इच्छा जताई थी। देश में एनएबीएल मान्यता प्राप्त करीब 51 जांचघर हैं और आईसीएमआर के प्रमुख मानक परिचालन प्रक्रिया के बारे में बताने की योजना बना रही है। निजी जांचघरों को संक्रमण पर नजर रखने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता करने के लिए सभी सूचनाएं तत्काल गण्य स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करनी होंगी। जांच से जुड़ी आवश्यक ज़रूरतें पूरी करने और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी), पुणे से जांच किट

सत्यापित कराने के बाद आईसीएमआर उन्हें कोरोनावायरस संक्रमण की जांच करने की अनुमति दे देगा। फिलहाल 8 जांच किट की पुख्ता पड़ताल हो रही है। हालांकि भार्गव ने निजी कंपनियों से जांच निःशुल्क करने की अपील की है। वैसे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार की तरफ से यह आग्रह नहीं कर रहे हैं। भार्गव ने कहा, 'आईसीएमआर निजी जांचघरों से अपील करती है कि उन्हें कोविड-19 की जांच बिना किसी शुल्क के करना चाहिए। वे इस राष्ट्रीय संकट में हमारी मदद करने के लिए आगे आए हैं।' उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जांच की निःशुल्क पेशकश कर पाएंगे। थायरोकेयर के चेयरमैन वे वेलमणि का मानना है कि कोविड-19 संक्रमण की निःशुल्क जांच संभव नहीं है, क्योंकि यह खासा महंगा होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर सरकार जांच के काम में आने वाले आवश्यक रसायनों की आपूर्ति करती है तो आम आदमी के लिए जांच का खर्च कम हो जाएगा।



कोरोना वायरस को नियंत्रित रखने के लिए घर के अंदर ही रहें।

आईबीए : राहत पैकेज की मांग

इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) वित्तीय क्षेत्र पर कोविड-19 के असर को न्यून करने के लिए बैंक कर्मचारियों तथा ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी करने का आग्रह है। साथ ही, आईबीए कोरोनावायरस के प्रसार से प्रभावित व्यवसायों के लिए राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई तथा भारत सरकार को भेजे जाने वाली सिफारिशों को तैयार कर रहा है। आईबीए के मुख्य कार्याधिकारी सुनील मेहता ने बताया कि आईबीए वित्तीय क्षेत्र तथा व्यवसायों पर

कोरोनवायरस के प्रभाव का विश्लेषण भी कर रहा है। एसोसिएशन ने सोमवार को बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की और इस मामले पर उनकी सिफारिशों पर चर्चा की। इस महीने की शुरुआत में केरल राज्य में एसबीआई के करंसी चेस्ट को बंद करना पड़ा था क्योंकि वहां कोरोनावायरस से ग्रस्त एक एनआरआई धन जमा करने के लिए आया था। यहां के कर्मचारियों को 31 मार्च तक के लिए अलग निगरानी में रखा गया है। बीएस

सरकारी दफ्तरों में सतर्कता

बीएस संवाददाता

देश में कोरोनावायरस फैलने की आशंका को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश भर में अपने कर्मचारियों, कार्यालयों और विभागों के लिए रोकथाम के उपाय जारी किए। नियमित रूप से जारी किए जाने वाले आंगतुक पास और अस्थायी पास तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि कार्यालय परिसरों में आंगतुक के प्रवेश को रोकना जाए। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सरकारी भवनों में प्रवेश स्थान पर थर्मल स्कैनर लगाने का आदेश भी दिया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी कार्यालय पत्र में कहा गया है, 'गैर-जरूरी कार्यालय यात्रा से बचें और अन्य कार्यालयों को फिजिकल फाइल और दस्तावेज भेजने से बचें।' वहीं भौंड नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने भी प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 10 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए 5,700 से अधिक लोगों की निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 40 लोग संक्रमित हुए हैं और मुंबई में एक मरीज की मौत हो गई जिससे देश में वायरस के प्रकोप से मरने वालों की तादाद तीन हो गई। देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों सामने आए हैं। इन संक्रमित लोगों में 22 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोनावायरस की वजह से प्रभावित दैनिक मजदूरी करने वालों के बैंक खाते में आरटीजीएस से सीधे कुछ पैसा डालेगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि सामुदायिक संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है।



फोटो: दलीप कुमार

दिल्ली: बजट होटलों में 90 फीसदी कमरे खाली

रामवीर सिंह गुर्जर

कोरोनावायरस ने दिल्ली के बजट होटलों के कारोबार की कमरतोड़ दी है। इन होटलों के 90 फीसदी कमरे खाली पड़े हैं। होटल उद्यमियों को खर्च निकालना भी दूधर हो गया है। जिससे उद्यमी एक तरफ कर्मचारियों को छंटनी करने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी भी कोरोना के डर से दिल्ली छोड़ रहे हैं। दिल्ली में 2,000-2,500 बजट होटल/गेस्ट हाउस हैं। जिनमें 50 से 60 हजार कमरे हैं। इन होटलों में 30 से 35 हजार कर्मचारी काम करते हैं। दिल्ली होटल ऐंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और करोलबाग के होटल उद्यमी संदीप खंडेलवाल ने बताया कि बजट होटलों के 90 फीसदी कमरे खाली पड़े हैं। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन, बिजली-पानी बिल, साफ-सफाई और तमाम कर व शुल्क आदि भी नहीं निकल रहे हैं।

अधिक कीमतों पर सतर्क ई-कॉमर्स

कोरोनावायरस महामारी के बीच ई-कॉमर्स कंपनियां एक ओर चुनौती से लड़ रही हैं, कृत्रिम तरीके से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ तथा साफ सफाई वाले उत्पादों की मांग में तेजी आने के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन उत्पादों की कीमतों में तेज इजाफा हो रहा है। एमेज़ॉन इंडिया ने मंगलवार को कहा, 'हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस महामारी के चलते उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच किसी भी उत्पाद की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि न हो। हमने हजारों उत्पादों को हटा दिया है।' वैश्विक स्तर पर एमेज़ॉन ने कोरोनावायरस संबंधित फर्जी दावा करने वाले लाखों उत्पादों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। दूसरी ओर, फ्लिपकार्ट का कहना है कि वह भले ही अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पाद की कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखती लेकिन कंपनी उत्पादों की उचित कीमत के मामले में विक्रेताओं के साथ करीब से काम कर रही है। दोनों कंपनियों वर्तमान में स्टॉक से बाहर हो चुकी आवश्यक वस्तुओं को प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस साझेदारों के साथ काम कर रहा है जिससे प्लेटफॉर्म पर हैंड सैनिटाइज़र, दस्ताने तथा मास्क जैसे ज़रूरी उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

बीएस

कई देशों ने सीमाएं कर दीं बंद

कोरोनावायरस की वजह से अमेरिका के शेरों में ऐतिहासिक गिरावट आई, दुनिया भर में कई सीमाओं को बंद किया गया और रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा दिख रही है। विभिन्न देशों की सरकारें इस वैश्विक आपदा को रोकने के लिए सख्त उपाय कर रही हैं। दुनिया भर में अब तक 1,82,000 लोग संक्रमित हो गए हैं जबकि 7,100 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,300 लोग

संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका के ओहायो प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी के लिए मतदान केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया। अमेरिका ने वैश्विक महामारी को रोकने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने पहली बार माना कि वैश्विक महामारी के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था संभवतः मंदी की ओर बढ़ सकती है जहां 1987 के बाद से पहली बार वॉल स्ट्रीट के शेयर करीब

13 प्रतिशत गिरकर सबसे निचले स्तर पर बंद हुए। अमेरिका की बड़ी विमानन कंपनियों ने कहा कि वह विमान सेवाओं में कम से कम 50 फीसदी की कटौती करेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो ने नागरिकों को आदेश दिया कि वह मंगलवार से लेकर अगले 15 दिनों तक घरे में ही रहें। मैक्रो ने कहा कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाएं मंगलवार से लेकर अगले 30 दिनों के लिए बंद रहेंगी। अब तक 145

शेयर बाजार: फिलीपींस में बंद, भारत में भी होगा ?

हाल में कई वैश्विक बाजारों में 20 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई और निवेशकों को 15 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ

समी मोडक

दुनिया भर में कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने से करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है और अब निवेशक इसे लेकर विचार कर रहे हैं कि क्या पूंजी में और ज्यादा नुकसान से बचने के लिए शेयर बाजारों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए। सोमवार को, फिलीपींस वित्तीय बाजारों में कारोबार अनिश्चितकाल के लिए बंद करने वाला पहला देश बन गया। फिलीपींस ने कोरोनावायरस की महामारी की वजह से पैदा हुए मंदी के हालात से बचने के लिए बाजारों में कारोबार बंद करने का कदम उठाया है। यह पहली बार नहीं है जब कारोबार को बंद किया गया है। 2001 में आतंकवादी हमलों (9/11) के बाद अमेरिकी बाजारों को एक सप्ताह तक बंद रखा गया था। इसी तरह, यूनान ने भी 2015 के यूरोपीय ऋण संकट के दौरान एक महीने से ज्यादा समय तक अपने बाजार को बंद रखा था। इसलिए अब यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या कारोबार बंद करना नियामकीय अधिकारियों के लिए एकमात्र विकल्प रह गया है ?

फिलीपींस के शेयर बाजार में इस साल 30 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है, जो एशिया में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर बाजारों में से एक है। बाजार बंद रखने की फिलीपींस की राह में श्रीलंका भी शामिल हो गया है।

विश्लेषकों की राय अलग अलग है। बाजार बंद रखने के खिलाफ नजरिया रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि इससे निवेशकों के लिए बाहर निकलने का अवसर समाप्त हो गया है, जबकि इसका समर्थन करने वालों का कहना है कि कोरोनावायरस महामारी शांत होने तक बाजारों को ब्रेक मिल सकता है। इक्विनोमिक्स रिसर्च एंड एडवायजर के मुख्य कार्याधिकारी जी चोकालिंगम का कहना है कि भारत जैसा बड़ा बाजार ऐसा कभी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, 'इससे साख समाप्त हो जाएगी और विदेशी निवेशक धारणा प्रभावित होगी।' एनवाईएसई की अध्यक्ष स्टेसी कनिंघम ने इस कदम का विरोध करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। उन्होंने कहा, 'बाजारों को खुला रखना और उनमें भी हंग से कामकाज बनाए रखना ज़रूरी है। बाजार मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हर किसी के द्वारा



महसूस की जा रही बड़ी अनिश्चितताओं का प्रतिबिंब है। बाजारों को बंद रखने से बाजार में गिरावट की मौजूदा प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आएगा, और साथ ही इससे निवेशक धारणा में पारदर्शिता कमजोर होगी तथा अपनी पूंजी तक निवेशकों की पहुंच घटेगी। इससे मौजूदा बाजार की चिंता में सिर्फ इजाफा ही होगा।

हाल के सप्ताहों में, कई वैश्विक बाजारों में 20 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई और इससे निवेशकों को 15 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। बाजार जानकारों का कहना है कि कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों को शेयरों की कीमतों को लेकर सही आकलन करना मुश्किल हो रहा है।

दक्षिण कोरिया के सोल के एक बैंक मुख्यालय में मुद्रा कारोबारी

हालांकि कई विश्लेषक फिलीपींस द्वारा उठाए गए कदम के पक्ष में दिख रहे हैं। आईजी एशिया में बाजार रणनीतिकार जिंजी पान ने ब्लूमबर्ग को बताया, 'यदि हालात में सुधार आता है तो यह बंदी बाजार के लिए सकारात्मक काम करेगी और अल्पावधि में अस्थिरता घटेगी, जैसा कि चीन ने किया, भले ही बाजार में शुरू में कुछ हद तक समायोजन की स्थिति देखने को मिले। कोरोनावायरस के प्रसार को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों को शेयरों की कीमतों को लेकर सही आकलन करना मुश्किल हो रहा है।

बालाजी मंदिर प्रशासन ने उठाए कई कदम

टी ई नरसिम्हन

कोरोनावायरस महामारी के बचाव के तौर पर विरमला स्थित बालाजी मंदिर का कामकाज देखने वाले तिरुमला तिरुपति देवास्थानम (टीटीडी) ने स्क्रीनिंग केंद्र तथा आइसोलेशन वार्ड बनाने, चिकित्सकों की टीम गठित करने का सख्त ही कदम उठाए हैं। मंगलवार से प्रशासन ने लंबी कतारों या प्रतीक्षाघरों में इंतजार करने के बजाय दर्शन के लिए टाइम स्लॉट देने की व्यवस्था शुरू की है। मंदिर प्रशासन के आधिकारिक

आंकड़ों के अनुसार 16 मार्च को 55,827 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए जबकि 15 मार्च को 63,747 तथा 14 मार्च को 78,872 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। देवस्थानम प्रशासन ने एक वक्तव्य में कहा, 'कोरोनावायरस को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद टीटीडी ने वैकुंठ के कॉम्प्लेक्स 1 एवं 2 में बैठकर श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन के लिए इंतजार करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। श्रद्धालुओं को समय जारी किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा आवंटित समय में सीधे भगवान वेंकटेश्वर के

दर्शन करने की सुविधा दी गई है।' तिरुमला तथा तिरुपति में श्रद्धालुओं को समय आवंटित करने के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं और केवल आवंटित समय में ही दर्शन के लिए पहुंचें। प्रशासन ने अनिवासी भारतीयों तथा विदेशियों से भी अनुरोध किया कि वे तिरुमला के लिए अपनी तीर्थयात्राएं स्थगित कर दें, साथ ही, सभी श्रद्धालुओं को मई 2020 तक दर्शन की तिथि स्थगित करने या टिकट रद्द करने की अनुमति दी है।



रूस के एक फूड बॉल के कर्मचारी

देशों में कोरोनावायरस फैल चुका है। स्पेन में मंगलवार को कोविड-19 के लगभग दो हजार नए मामलों की पुष्टि हुई और इसी के साथ देश में कोरोनावायरस से

संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो गई। इस बीमारी से अब तक 491 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में मंगलवार को कोरोनावायरस संक्रमण से पहली मौत दर्ज की गई जबकि देश में इस वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 193 पर पहुंच गया। ईरान में कोरोना वायरस से 135 और लोगों की मौत हो गई और इस तरह मरने वालों की तादाद 988 तक पहुंची। यूरो 2020 फुटबाल टूर्नामेंट 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक कोपा अमेरिका 2020 के बजाय अब 2021 में होगा।

एजेंसियां